मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | भोपाल, शनिवार 19 सितंबर 2026 | वर्ष-08, अंक-304, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

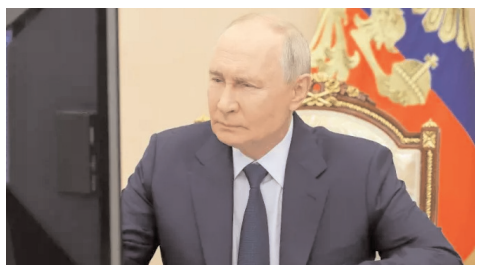

पुतिन की जीत तय, फिर भी रूस में चुनाव यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में भी वोटिंग

मॉस्को। रूस में शुक्रवार यानी 18 सितंबर से तीन दिन का संसदीय चुनाव शुरू हो गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया का संसद में दबदबा बरकरार रहने की उम्मीद है। वहीं, यूक्रेन युद्ध का खुलकर विरोध करने वाली याब्लोको पार्टी को चुनाव से बाहर कर दिया गया है। यह 2022 में यूक्रेन पर रूस के पूर्ण सैन्य हमले के बाद पहला संसदीय चुनाव है। रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों में भी वोटिंग हो रही है। यूक्रेन और यूरोपीय संघ ने वहां हो रहे मतदान को अवैध बताया है। क्रेमलिन के लिए यह चुनाव सिर्फ संसद के सदस्य चुनने तक सीमित नहीं है। पुतिन चाहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वोट डालें, ताकि यह संदेश जाए कि यूक्रेन युद्ध के बीच भी जनता सरकार और रूसी सैनिकों के साथ खड़ी है। पुतिन ने शुक्रवार को ऑनलाइन वोट डाला। चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि लोगों का फैसला दिखाएगा कि लाखों लोग रूस के सैनिकों के साथ खड़े हैं और देश एकजुट है।

450 सीटों के लिए हो रही वोटिंग

रूस के स्टेट ड्यूमा में 225 सीटों पर लोग राजनीतिक पार्टियों को वोट देंगे। बाकी 225 सीटों पर अलग-अलग इलाकों से खड़े उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनेंगे। यूनाइटेड रशिया के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी, एलडीपीआर, ए जस्ट रशिया और न्यू पीपल जैसी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि, इन्हें रूस में सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्ष नहीं माना जाता। बड़े मुद्दों पर ये पार्टियां अक्सर सरकार का साथ देती हैं।
याब्लोको रूस की एकमात्र रजिस्टर्ड पार्टी थी, जो खुले तौर पर यूक्रेन युद्ध का विरोध करती रही है। पार्टी जंग खत्म करने और बातचीत के जरिए शांति की बात करती है। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में याब्लोको की उम्मीदवारों की सूची का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। कोर्ट के मुताबिक, पार्टी ने चुनाव प्रचार में ऐसे लोगों से मिले पैसे का इस्तेमाल किया, जिन्हें विदेश से पैसा मिला था।

सेमीकॉन इंडिया-2026 में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेमीकंडक्टर कंपनियों से किया संवाद

सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश के लिए प्रदेश में अपार संभावनाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली के यशोभूमि स्थित सेमीकॉन इंडिया 2026 में मध्यप्रदेश पवेलियन का भ्रमण कर सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने मध्यप्रदेश में निवेश, तकनीकी सहयोग और सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विस्तार की संभावनाओं पर उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार उद्योगों को आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने पारस सेमीकंडक्टर्स, थॉमसन सेमीकंडक्टर्स, स्प्रिन्टोनिक्स एआई, एनएक्सपी इंडिया, मार्वल सेमीकंडक्टर्स, एल एंड टी सेमीकंडक्टर्स और स्वदेश आईसी सेमीकंडक्टर्स सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया।

वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा

मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रुप (आईएसआईजी) के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में जापान की एक्रेटेक, केनन और कैइजो, कोरिया की हनवा और जेनसेम इंक तथा अमेरिका की मेकडरमिड अल्फा के प्रतिनिधि शामिल थे। जापानी प्रतिनिधिमंडल में आक्साईड कापोर्रेशन, स्केल फोटोनिक्स और इम्प्यूट इंक के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया-2026 वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के साथ संवाद और सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। मध्यप्रदेश अपनी औद्योगिक क्षमता, निवेश की संभावनाओं और उपलब्ध संसाधनों के साथ इस क्षेत्र में नई साझेदारियों के लिए तैयार है।

मुख्यमंत्री ने किष्किंधा इंटरनेशनल, डिजिकॉम, सिग्निटयूट, स्टेम्बो टेक्नोलॉजी, टू-चिप सोल्युशन, बनाश्री सेमीकंडक्टर्स, वीएलएसआई एक्सपर्ट और न्यूजिमो सेमीकंडक्टर्स सहित चिप डिजाइनिंग एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मोहाली चिप डिजाइनिंग पेवेलियन और स्वीडिश पेवेलियन का भी अवलोकन किया। सेमीकॉन इंडिया-2026 के दौरान हुई इन बैठकों में मध्यप्रदेश में सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइनिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर संवाद हुआ।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में निवेश को लेकर राज्य सरकार अपनी नीतियों के आधार पर प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सभी प्रकार से अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार देश-विदेश में इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिये निवेशकों को अपनी आकर्षक पॉलिसी के माध्यम से राज्य में इन्वेस्टमेंट के लिए मौका भी दे रही है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-2025) के दौरान भी सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े निवेशकों को आमंत्रित किया गया था।

मध्यप्रदेश के इंदौर में 23-24 अक्टूबर को होगा बड़ा निवेशक सम्मेलन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार लगातार देश और विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रही है। नई दिल्ली के सेमिकॉन इंडिया-2026 में मध्यप्रदेश सरकार की ओर से एक स्टॉल लगाया गया है, जहां प्रदेश के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों और कारोबारी प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर रुचि बढ़ी है। मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में निवेश का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका में हो रहे सेमीकॉन इंडिया-2026 में स्थापित मध्यप्रदेश पवेलियन के भ्रमण के उपरांत स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी 23 और 24 अक्टूबर को इंदौर में एक बड़ा निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े निवेशकों को मध्यप्रदेश में निवेश के अवसरों और राज्य की नीतियों से अवगत कराया जाएगा।

आतंकी विस्फोटक से भरी गाड़ी लेकर टकराया

पाकिस्तान में नमाज के दौरान आत्मघाती हमला, 16 मौतें

एजेन्सी, **इस्लामाबाद**

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में शुक्रवार की नमाज के दौरान मस्जिद के पास धमाका हुआ। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 5 पुलिसकर्मी और 11 आम नागरिक शामिल हैं।
धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद के बाहर का हिस्सा पूरी तरह टूट गया। धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक, शुरूआती जांच में सामने आया है कि पुराने पुलिस लाइंस के गेट पर विस्फोटक से भरी एक गाड़ी टकराई थी। पाकिस्तान में जनवरी से अब तक 990 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इनमें 1,129 लोगों की मौत हो चुकी है।
घटना के बाद पुलिस और हमलावरों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार, धमाके के बाद 7 आतंकियों ने पुलिस लाइंस परिसर में घुसने की कोशिश की थी। 6 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें एक आत्मघाती हमलावर भी शामिल है। हमले की जिम्मेदारी इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम के आतंकी गठबंधन ने ली है। यह संगठन पिछले साल बना था और इसमें पाकिस्तान के कई उग्रवादी गुट शामिल हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना बेहद गलत है और इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

पांच मिनट की गूगल मीट कॉल में 80 नौकरियां खत्म

अमेरिकी कंपनी ने पूरी भारतीय कस्टमर सर्विस टीम हटाई

एजेन्सी, **नई दिल्ली**

अमेरिकी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लू वाइन ने महज पांच मिनट की गूगल मीट कॉल में 80 लोगों की अपनी पूरी भारतीय कस्टमर सर्विस टीम को ही निकाल बाहर किया है। आर/इंडिया वर्कप्लेस कम्युनिटी में एक प्रभावित कर्मचारी ने अपना दर्द साझा करते हुए घटना की पूरी जानकारी दी है। कर्मी ने बताया कि छंटनी वाले दिन मैनेजमेंट ने सभी 80 कर्मचारियों को ऑपरेशनल कारणों (कामकाजी वजहों) का हवाला देकर ऑफिस आने के बजाय घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने के लिए कहा था।
कर्मचारी अपनी शाम 6:30 बजे की सामान्य शिफ्ट कर रहे थे। शिफ्ट शुरू होने के ठीक 3 घंटे बाद, रात 9:30 बजे अचानक पूरी टीम को एक गूगल मीट लिंक के जरिये वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने को कहा गया। मीटिंग शुरू होते ही सीनियर मैनेजमेंट ने बिना किसी पूर्व चेतावनी या नोटिस के सीधे तौर पर कह दिया कि पूरी भारतीय कस्टमर सर्विस टीम को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जा रहा है। यह पूरी बातचीत महज 5 मिनट में खत्म हो गई।
प्रबंधन ने कथित तौर पर प्रदर्शन से जुड़ी समस्याओं (परफॉरमेंस इश्यू) और अपेक्षाओं के अनुरूप आउटपुट न मिलने का हवाला दिया है। प्रभावित कर्मचारियों ने इन आरोपों को नकारा है और सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की है।

डिजिटल बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता है कंपनी

अमेरिकी कंपनी डिजिटल बैंक और वित्तीय सेवा प्रदाता है। यह अमेरिका में छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को बैंकिंग, लोन और पेमेंट जैसी वित्तीय सेवाएं देती है। इस कंपनी का मुख्यालय न्यू जर्सी में है। कंपनी में वैश्विक स्तर पर करीब 1,000 कर्मचारी है। भारत में काम कर रही इसकी पूरी कस्टमर सपोर्ट यूनिट में 80 कर्मचारी थे, जिन्हें एक साथ इस कॉल के जरिये निकाला गया।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले...

दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस का इतिहास पढ़ें

एजेन्सी, **नई दिल्ली**

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के बयानों को दुर्भावना-प्रेरित बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ कुछ बोलने से पहले उन्हें अपनी पार्टी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए।
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न को जब्त किए जाने के मुद्दे पर श्री गांधी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज उन्होंने (श्री गांधी) एक अद्भुत ट्वीट किया है, जिससे लगता है कि उन्हें अपनी पार्टी के बारे में भी कुछ नहीं पता है। वह भाजपा पर आरोप लगाने की प्रक्रिया में यह भी ध्यान नहीं दे पाते कि जिन पार्टियों का का वह नाम ले रहे हैं, वे पार्टियां कौन हैं। श्री गांधी ने आज ट्वीट किया कि पहले

शिवसेना, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और अब तृणमूल कांग्रेस को भाजपा खत्म कर रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि श्री गांधी राकांपा का पूरा नाम भी नहीं पढ़ सकते हैं, जो कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। श्री शरद पवार ने 1999 में विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग होकर राकांपा बनाई थी लेकिन विदेशी मूल के वारिस श्री गांधी को अपनी ही पार्टी की जड़ों की जानकारी नहीं है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि इसी तरह 1997 में कांग्रेस के अंदरूनी हालात से निराश होकर सुश्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दिया।

नंदीग्राम उपचुनाव से ममता की कैंडिडेट भी पीछे हटीं, बंगाल सीएम शुभेंदु से की थी मुलाकात

ममता के समर्थन के 2 घंटे बाद कांग्रेस कैंडिडेट गिरफ्तार

एजेन्सी, **नई दिल्ली**

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव से 18 दिन पहले ममता गुट की महिला कैंडिडेट संचिता प्रधान डे ने शुक्रवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन वापस ले लिया है। संचिता ने इससे पहले बंगाल सीएम शुभेंदु से मुलाकात की थी। इसके बाद ममता ने नंदीग्राम में कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को समर्थन देने की बात कही। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने दावा किया कि इसके 2 घंटे बाद बंगाल पुलिस ने मिलन को एक पुराने केस में अरेस्ट कर लिया।
नंदीग्राम सीट मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने खाली की थी। रेजीनगर सीट हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद खाली हुई। दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को चुनाव होगा, रिजल्ट 9 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस ने दावा किया कि नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए उसके उम्मीदवार मिलन प्रधान को 19 साल पुराने केस में अरेस्ट किया गया है।

नंदीग्राम लंबे समय से TMC और भाजपा के बीच राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है। इस क्षेत्र में 2007 के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने ममता बनर्जी और TMC को 2011 में सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 2021 में ममता ने यहीं से बंगाल के मौजूदा सीएम शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। अधिकारी BJP में शामिल होने के बाद TMC के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन चुके हैं।
2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के साथ भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत दर्ज की। भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से हराया। अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले।
बाद में अधिकारी ने भवानीपुर सीट अपने पास रखी और नंदीग्राम से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नंदीग्राम सीट खाली हुई।

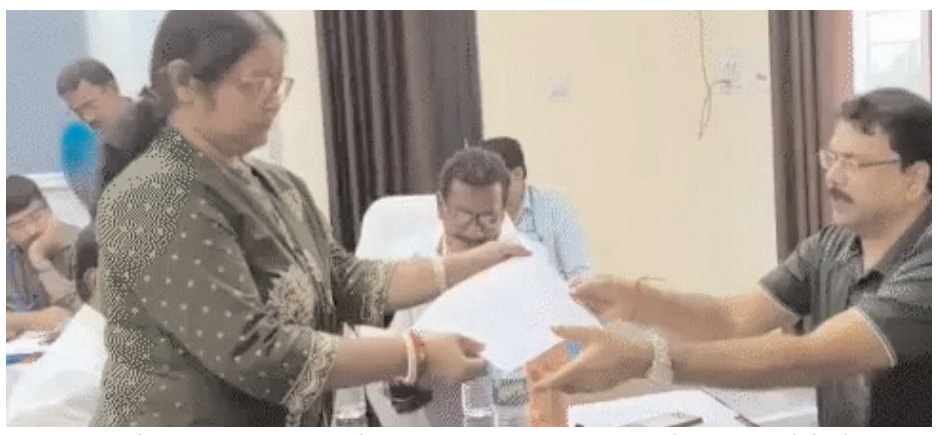

ममता बनर्जी की पार्टी का नाम 'ममता टीएमसी': बागी गुट 'डेमोक्रेटिक टीएमसी'

बंगाल में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से 18 दिन पहले चुनाव आयोग ने TMC के दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं। ममता बनर्जी के गुट को ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी का चिह्न मिला है, जबकि दूसरे गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस और लिफाफा दिया गया है। इससे एक दिन पहले आयोग ने दोनों गुटों को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और फूल-घास वाला मूल चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने से रोक दिया था। यह अंतरिम व्यवस्था है। मूल नाम और चिह्न पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। अब दोनों गुट उपचुनाव में नई पार्टी नाम और सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम और रेजीनगर पर 6 अक्टूबर को वोटिंग हैं और रिजल्ट 9 अक्टूबर को आएगा। चुनाव आयोग के फैसले पर ममता ने कहा- EC मेरी पार्टी का वह चुनाव चिह्न कैसे फ्रीज कर सकता है जो 28 साल से हमारे पास है। ना तो हम सिर झुकाएंगे और ना ही हार मानेंगे; हम लड़ेंगे और वापसी करेंगे।

युवाओं के विकास की इन्द्रधनुषी रणनीति

युवा, मध्यप्रदेश के सामर्थ्य का जीवन्त प्रतीक हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को, निवेश और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया था, वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष है और अब इसे आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में, मनाने का निर्णय लिया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास और कल्याण के लिए, मोहन सरकार ने इन्द्रधनुषी रणनीति का निर्माण किया है, जिसके 07 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं-

राज्य सरकार ने 85 हजार से अधिक युवाओं की. शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां की है। इसी प्रकार अगले 01 वर्ष में 01 लाख से अधिक युवाओं को आईटीआई में तथा प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में कौशल प्रशिक्षण दिलाने का काम करेगी। कौशल विकास के अंतर्गत, मध्यप्रदेश में एक अलग प्लेसमेंट सेल बनाया जाएगा, जो उद्योग और सरकार के बीच, एक कड़ी का काम करेगा।

रणनीति के 7 महत्वपूर्व स्तंभ

- गुणवत्तायुक्त शिक्षा
- कौशल विकास
- उद्यमिता एवं स्वरोजगार
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर
- स्टार्टअप्स को सहयोग
- खेल, कला, संस्कृति, शोध एवं अनुसंधान प्रोत्साहन
- नेतृत्व क्षमता विकास

उद्यम पोर्टल पर विगत ढाई वर्षों में, 3 लाख 34 हजार से अधिक विनिर्माण ईकाईयां पंजीकृत हुई, जिनमें 33 लाख 80 हजार युवाओं को, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। वृहद औद्योगिक ईकाईयों में भी, 50 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।

राज्य सरकार अगले ढाई वर्ष में, उन युवाओं पर विशेष रूप से फोकस करने जा रही है, जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है। ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर, उन्हें इतना सशक्त बनाया जाएगा कि वे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश जाकर भी रोजगार प्राप्त कर सके।

युवाओं को केन्द्र में रखकर, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्यप्रदेश M S M E विकास नीति 2025', 'स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025' नीति लागू की गई। वर्तमान में लगभग 8 हज़ार स्टार्टअप संचालित हैं, इसमें से 50 प्रतिशत स्टार्टअप का नेतृत्व, नारी शक्ति, कर रही है। प्रदेश के हर जिले में, कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जायेगा। आगामी ढाई वर्षों में स्टार्ट-अप की संख्या 12 हजार से अधिक और 100 नवीन इन्क्यूबेशन

सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य है। 'प्लग-एंड-प्ले' मॉडल पर, को-वर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेसटेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में, एमएसएमई की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालीन मामलों की, त्वरित सुनवाई और निराकरण के लिए, राज्य सरकार ने 04 'फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

18.95 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को 189 करोड़ छात्रवृत्ति

3.18 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को 556 करोड़ की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कक्षा 01 से 10 में वर्ष 2003 से अभी तक लगभग 3,96,24,580 (तीन करोड़ छियानवे लाख चौबीस हज़ार पांच सौ अस्सी) एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2003 से वर्ष 2025-26 तक लगभग 58,02,143 (अट्ठावन लाख दो हज़ार एक सौ तिरालीस) इस प्रकार लगभग 4,54,26,723 (चार करोड़ चौवन लाख छब्बीस हज़ार सात सौ तेईस) विद्यार्थियों लाभान्वित किया गया है।

51 विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के मौके

विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत विदेश में अध्ययन के लिए प्रति विद्यार्थी, प्रतिवर्ष 40 हजार यू.एस. डॉलर कोचिंग शुल्क एवं 10 हजार यू.एस. डॉलर जीवन निर्वाह भत्ता एवं अन्य आकस्मिक भत्ते हेतु राशि प्रदान की जाती है।

विगत 09 वर्षों में 51 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन स्थित विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन प्राप्त किया जा रहा है।

छात्रावास जनजातीय कार्य विभाग द्वारा कुल 2671 छात्रावास एवं आश्रम शालाओं का संचालन किया जा रहा है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राशि रूपये 7 सौ 27 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर 10 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन स्वीकृत किये गये है।

प्रतिभा योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित संस्थाओं IIT, NIT, NLIU, शासकीय मेडिकल कॉलेज में चयन होने पर पुरस्कार राशि प्रदाय की

जाती है। इस योजना में वर्ष 2025-26 में 272 विद्यार्थियों को राशि रूपये 71 लाख वितरित की गई। मध्यप्रदेश स्पेशल एण्ड रेसीडेंशियल एकेडमिक सोसायटी के द्वारा 71 एकलव्य आदर्श आवासीय, 82 माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर एवं 08 आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में 61 हजार से अधिक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है।

19 जनजातीय बहुल जिलों में 94 सांदीपनि विद्यालय

सांदीपनि विद्यालय

कुल भवन	274
निर्माणाधीन भवन	167
पूर्ण हो चुके भवन	97
लोकार्पित विद्यालय	74
लोकार्पण के लिए तैयार	23

सांदीपनि विद्यालय शिक्षा की गुणवता में सुधार हेतु नवीन शिक्षा नीति के दृष्टिगत सर्व संसाधन संपन्न विद्यालयों की स्थापना के लिए योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 19 जिलों में 94 सांदीपनि विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों के 55 भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है एवं 39 भवन निर्माणाधीन है।

निर्माण :- आश्रम शाला/जूनियर छात्रावास/सीनियर छात्रावास/महाविद्यालयीन छात्रावास, माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर, क्रीडा परिसर एवं सांदीपनि विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य के लिए वितीय वर्ष 2026-27 में पूंजीगत मद में राशि रु. 1 हजार 7 सौ 37 करोड का बजट प्रावधान किया गया है।

जनजातीय उपयोजना :- अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विभागों के माध्यम से आर्थिक, मानव संसाधन, क्षेत्र विकास एवं अन्य विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे है। संबंधित विकास विभागों द्वारा जनजातीय उपयोजना अंतर्गत प्रावधानित बजट एवं व्यय की राशि का अनुश्रवण जनजातीय कार्य विभाग के स्तर पर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनजातीय उपयोजना अंतर्गत राशि रु. 37350 करोड का व्यय किया गया। वर्ष 2026-27 में 47428 करोड का प्रावधान किया गया है।

पिछड़ा वर्ग के 5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभांवित

13 हजार करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और निर्णयों के फलस्वरूप प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के हर स्तर पर अभूतपूर्व प्रोत्साहन और वित्तीय सहयोग मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से विदेश अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति, नि:शुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पिछले 15 वर्षों में 13 हजार 156 करोड़ 51 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है। योजनाओं से लगभग 5 करोड़ 34 लाख 39 हजार 54 से अधिक विद्यार्थी लाभांवित हुए।

प्री एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति से मदद

स्कूली स्तर पर ड्रॉप-आउट दर को समाप्त करने और बच्चों की पढ़ाई निरंतर बनाए रखने के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2026-27 तक पिछड़ा वर्ग के 4 करोड़ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को ₹ 2,535 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले होनहारों को 'प्रावीण्य (मेधावी) छात्रवृत्ति योजना' के तहत पिछड़ा वर्ग के 2,185 विद्यार्थियों को 1 करोड़ 69 लाख रूपये की राशि दी गई है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में कॉलेज स्तर के छात्रों को राहत देते हुए 'पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के तहत वर्ष 2012-13 से 2026-27 के दौरान इसी वर्ग के 84.22 लाख विद्यार्थियों को ₹10,467 करोड़ की राशि से संबल प्रदान किया गया है।

अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर

84 छात्रवासों के लिए 420 करोड़

शिक्षा को बढ़ावा देने म.प्र. सरकार ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं उत्कृष् 8 छात्रावास के रूप में 1933 छात्रावासों का संचालन कर रही है। इनमें एक लाख से अधिक सीट स्वीकृत है। अनुसूचित जाति छात्रावास भवनों का निर्माण, आवास सहायता योजना, छात्रावासों के लिए उत्कृष्टता पुरुस्कार योजना, छात्रावासों में पुस्तकालय योजना, प्रसाधन किट प्रदाय योजना, दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास सुविधा को गुणवत्ता सहित लागू कर अनुसूचित जाति के युवाओं की शिक्षा के स्तर का उन्नयन किया जा रहा है। इस वर्ष राशि रु. 420.00 करोड़ के 84 छात्रावास के नवीन भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर महाविद्यालयीन स्तर तक की शिक्षा को सुगम बनाये जाने हेतु विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँ संचालित की जा रही है। वर्ष 2025-26 में कक्षा 1 से 12 तक के लिये 13 लाख 37 हजार विद्यार्थियों को राशि रु. 73.71 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। महाविद्यालय स्तर के लिये 2 लाख 09 हजार विद्यार्थियों को राशि रु. 344.02 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

D-11118/26

गुना प्रधान डाकघर का हुआ कायाकल्प, गुना प्रधान डाकघर का आधुनिक स्वरूप नागरिकों को किया समर्पित

डाकघर बदल रहा है, बदलते भारत की नई तस्वीर बन रहा है : ज्योतिरादित्य सिंधिया

■ एक सत बुलेटिन, **गुना।**

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री सह स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डाकघर आज केवल डाक पहुंचाने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह आधुनिक भारत के जनसेवा केंद्र के रूप में तेजी से बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है और उसी बदलाव के साथ भारतीय डाक भी बदल रहा है। कभी डाकिया चिट्ठी लेकर घर तक पहुंचता था, आज वही डाक व्यवस्था डिजिटल सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पासपोर्ट, आधार, पार्सल, बीमा और बैंकिंग जैसी अनेक सुविधाओं को नागरिकों के और करीब ला रही है। इसी बदलते डाकघर की तस्वीर गुना प्रधान डाकघर में भी दिखाई दे रही है। वे गुना प्रधान

डाकघर के जनसेवा कनेक्ट थीम पर तैयार सेवाएं के लोकार्पण के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। भारत सरकार की आधुनिक डिजाइन अवधारणा और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधान डाकघर के भवन का कायाकल्प किया गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि गुना प्रधान डाकघर का यह नया रूप केवल भवन का सौंदर्यीकरण नहीं है, बल्कि बदलती डाक व्यवस्था का प्रतीक है। हमारा प्रयास है कि जब कोई नागरिक डाकघर आए तो उसे बेहतर वातावरण, आधुनिक सुविधाएं और सरल

एवं त्वरित सेवाएं एक ही स्थान पर मिलें। सिंधिया ने नवनिर्मित डाकघर की सुव्यवस्थित टोकन प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से ग्राहकों को बिना भीड़ के अपनी बारी के अनुसार सेवाएं प्राप्त होंगी। हमारा प्रयास है कि जब कोई नागरिक डाकघर आए तो उसे बेहतर वातावरण, आधुनिक सुविधाएं और सरल एवं त्वरित सेवाएं एक ही स्थान पर मिलें। सिंधिया ने नवनिर्मित डाकघर की सुव्यवस्थित टोकन प्रणाली की जानकारी देते हुए बताया कि इसके माध्यम से ग्राहकों को बिना भीड़ के अपनी बारी के अनुसार सेवाएं प्राप्त होंगी।प्रत्येक टोकन पर एक नंबर अंकित होगा, जो ग्राहक को संबंधित नंबर वाले काउंटर तक निर्देशित करेगा। इसके साथ ही डाकघर में डिजिटल स्क्रीन भी लगाई गई है, जिस पर विभिन्न सेवाओं के लिए निर्धारित समय की जानकारी प्रदर्शित होगी। उदाहरण के तौर पर, डुप्लीकेट पासबुक जारी करने की सेवा में केवल एक दिन का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि आज डाक विभाग डिजिटल इंडिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। डिजिटल तकनीक के विस्तार के कारण नागरिकों को अनेक सेवाओं के लिए बार-बार डाकघर आने की आवश्यकता नहीं है। 'डाक सेवा' और 'डाक मित्र' जैसे डिजिटल माध्यमों से अनेक सेवाओं का लाभ घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है।

सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, निशातपुरा, भोपाल में राजभाषा पखवाड़ा-2026 एवं 'हिंदी में हस्ताक्षर करें'

कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 89वीं तिमाही बैठक आयोजित हुई

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, निशातपुरा, भोपाल में राजभाषा पखवाड़ा-2026 एवं 'हिंदी में हस्ताक्षर करें' अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं उप मुख्य यांत्रिक अभियंता, सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना, भोपाल श्री पी.एस. रघुवंशी द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर कर किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में समिति अध्यक्ष श्री पी.एस. रघुवंशी ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके पश्चात 16 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए जाने वाले 'राजभाषा उत्सव' का आगाज 'हिंदी में हस्ताक्षर करें' अभियान के

माध्यम से किया गया। इसके उपरांत कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून 2026 को समाप्त तिमाही की 89वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक के प्रारंभ में कार्य प्रबंधक श्री अक्षय गंगरवाल ने पौधा भेंटकर समिति अध्यक्ष श्री पी.एस. रघुवंशी का स्वागत किया। तत्पश्चात संपर्क राजभाषा अधिकारी एवं सहायक कार्मिक अधिकारी श्री संदीप शर्मा ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कार्यालय में आयोजित किए जाने वाले राजभाषा पखवाड़े के अंतर्गत प्रस्तावित विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा बैठक की रूपरेखा के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री पी.एस. रघुवंशी ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि कारखाने में राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार का कार्य पूर्ण निष्ठा और सक्रियता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम 'क' क्षेत्र में निवास करते हैं तथा हिंदी हमारी राजभाषा होने के साथ-साथ मातृभाषा भी है। ऐसे में भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 'हम जो परिकल्पना अपनी भाषा में कर सकते हैं, वह दूसरी भाषा में संभव नहीं है, फिर चाहे हम उस भाषा में कितने ही निपुण क्यों न हों।' श्री रघुवंशी ने कहा कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी होने के नाते राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों, शॉप एवं अनुभाग प्रभारियों को राजभाषा हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी देते हुए हिंदी के विकास, प्रयोग एवं प्रसार में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग का प्रतिशत बढ़ाने के संबंध में अपने रचनात्मक सुझाव भी साझा किए। उन्होंने राजभाषा अनुभाग द्वारा आयोजित 'हिंदी में हस्ताक्षर करें' अभियान की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जिले में अब तक 59 निरीक्षण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिले के विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं जनसुविधाओं का मैदानी निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के लिए 18 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभियान के तहत राशन दुकानों, शासकीय अस्पतालों, छात्रावासों, विद्यालयों, आंगनवाड़ियों सहित विभिन्न शासकीय संस्थानों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संस्थानों में उपलब्ध व्यवस्थाओं, सेवाओं और आवश्यक सुविधाओं का परीक्षण किया तथा निर्धारित जानकारी दर्ज की। निरीक्षण प्रक्रिया को District GIS Parakh Application के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। अधिकारी निरीक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी और फोटोग्राफ एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहे हैं। इससे निरीक्षण कार्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा रही है। अभियान के तहत गत 11 सितंबर को नगर पालिका परिषद बेरसिया का भी निरीक्षण किया गया था। जिले में अब तक कुल 59 निरीक्षण किए जा चुके हैं। जिला स्तर पर अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

15 वर्ष में पिछड़ा वर्ग के 5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभांवित, 13 हजार करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और निर्णयों के फलस्वरूप प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के हर स्तर पर अभूतपूर्व प्रोत्साहन और वित्तीय सहयोग मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा से विदेश अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में पिछले 15 वर्षों में 13 हजार 156 करोड़ 51 लाख से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है। योजनाओं से लगभग 5 करोड़ 34 लाख 39 हजार 54 से अधिक विद्यार्थी लाभांवित हुए। स्कूली स्तर पर ड्रॉप-आउट दर को समाप्त करने और बच्चों की पढ़ाई निरंतर बनाए रखने के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2026-27 तक पिछड़ा वर्ग के 4 करोड़ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 2,535 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट अंक लाने वाले होनहारों को 'प्रावीण्य (मेधावी) छात्रवृत्ति योजना' के तहत पिछड़ा वर्ग के 2,185 विद्यार्थियों को 1 करोड़ 69 लाख रूपये की राशि दी गई है। उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में

कॉलेज स्तर के छात्रों को राहत देते हुए 'पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' के तहत वर्ष 2012-13 से 2026-27 के दौरान इसी वर्ग के 84.22 लाख विद्यार्थियों को 10,467 करोड़ की राशि से संबल प्रदान किया गया है। पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रशासनिक और प्रतियोगी सेवाओं में सफलता दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में प्रारंभ की गई 'सरदार पटेल कोचिंग प्रशिक्षण योजना' के तहत 11,174 शिक्षित युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 23 करोड़ 9 लाख रूपये के व्यय से निशुल्क कोचिंग दी गई है।

राजुरकर राज स्मृति सम्मान विनय उपाध्याय को

भोपाल। इस वर्ष का राजुरकर राज स्मृति सम्मान भोपाल और देश के प्रतिष्ठित उद्बोधक और संपादक विनय उपाध्याय को प्रदान किया जा रहा है ।यह आयोजन 27 सितंबर को दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की राज सदन में होगा । उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को दुष्यन्त कुमार स्मारक पाण्डुलिपि संग्रहालय के संस्थापक राजुरकर राज के निधन के पश्चात उनकी स्मृति में यह सम्मान प्रतिवर्ष दिया जा रहा है । पूर्व में यह सम्मान राकेश पांडे- दिल्ली , पद्मश्री विजयदत्त- भोपाल और यूनुस खान - मुंबई को प्रदान किया जा चुका है ।इस सम्मान में 11000 की सम्मान निधि, शाल श्रीफल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि राजुरकर राज और विनय उपाध्याय समकालीन रहे हैं और उनकी मित्रता भी प्रगाढ़ रही है।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, झाबुआ और आलीराजपुर में नागरिक बनाएंगे ह्यूमन रंगोली

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

सेवा, सहभागिता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के अवसर पर 9 और 10 अक्टूबर को विशेष आयोजन किया जाएगा। 'सेवा के रंग–राष्ट्र के संग' थीम पर प्रदेश के छह जिलों में बड़े मैदानों पर विशाल ह्यूमन रंगोली बनाई जाएगी। इस अनूठे आयोजन में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता होगी और मानव रंगोली के माध्यम से सेवा, राष्ट्रभावना, स्थानीय संस्कृति तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जाएगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, झाबुआ और आलीराजपुर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जनभागीदारी को प्रमुख आधार बनाया गया है। हजारों नागरिक एक निर्धारित स्वरूप में एक साथ खड़े होकर ऐसी जीवंत मानव रंगोली का निर्माण करेंगे, जिसे ऊपर से देखने पर एक विशाल चित्र और संदेश के रूप में देखा जा सकेगा। आयोजन के दौरान ड्रोन कैमरों के माध्यम से इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड किया जाएगा। 'सेवा के रंग–राष्ट्र के संग' कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा को केवल एक गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ना है। आयोजन में स्थानीय कला और लोक-संस्कृति को भी स्थान दिया जाएगा। इसके साथ विकसित भारत के संकल्प और देश की प्रगति का संदेश भी मानव रंगोली के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन में मध्यप्रदेश की स्थानीय कला एवं लोक-संस्कृति को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने की योजना है। विशाल मानव रंगोली के निर्माण के दौरान ड्रोन शूटिंग के जरिए ऊपर से पूरे आयोजन की तस्वीर सामने आएगी। इससे अलग-अलग जिलों में होने वाली जनभागीदारी का व्यापक दृश्य तैयार होगा और सेवा संकल्प का संदेश व्यापक स्तर तक पहुंचाया जा सकेगा।

वन विभाग के नेतृत्व में समन्वय

'सेवा के रंग–राष्ट्र के संग' कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर पर नोडल अनुसूचित जाति मंत्री श्री नागर सिंह चौहान रहेंगे। राज्य प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती जी.वी. रश्मि को दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है, जबकि जनसंपर्क विभाग और संबंधित छह जिलों का जिला प्रशासन आयोजन में सहयोगी भूमिका निभाएगा।

14 लाख रुपये के ऋण और 35 प्रतिशत अनुदान से स्थापित की आधुनिक मशीनें

प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से सरिता के हुनर को मिली नई उड़ान

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में स्वरोजगार को मिल रहे प्रोत्साहन से भोपाल जिले की श्रीमती सरिता कुशवाह ने अपने हुनर को सफल उद्यम में बदलकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है। कभी पूंजी और आधुनिक संसाधनों के अभाव में सीमित स्तर पर व्यवसाय करने वाली सरिता आज आधुनिक मशीनों, आकर्षक पैकेजिंग और बेहतर ब्रांडिंग के साथ मसाला एवं कच्ची घानी तेल प्रसंस्करण इकाई का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। हुनर था, पूंजी की कमी रोक रही थी कदम भोपाल जिले के फंदा विकासखंड की निवासी श्रीमती सरिता कुशवाह को मसाले और कच्ची घानी तेल तैयार करने का हुनर पहले से था। उनके मन में अपने व्यवसाय को विस्तार देने का सपना भी था, लेकिन आधुनिक मशीनें खरीदने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं थी। सीमित संसाधनों के कारण उनका व्यवसाय छोटे स्तर तक सिमटा हुआ था और मेहनत के अनुरूप आमदनी भी नहीं हो पा रही थी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना बनी बदलाव का आधार सरिता के जीवन में बदलाव की शुरुआत तब हुई, जब उन्हें उद्यानिकी विभाग, जिला भोपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की जानकारी मिली। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने मसाला एवं कच्ची घानी तेल प्रसंस्करण व्यवसाय के विस्तार के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन किया। वर्ष 2025-26 में यूको बैंक, भोपाल द्वारा सरिता को 14 लाख रुपये का बैंक ऋण स्वीकृत किया गया। योजना के अंतर्गत उन्हें ऋण राशि पर 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ भी मिला। वित्तीय

सहायता प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने परंपरागत हुनर को आधुनिक और व्यवस्थित व्यवसाय का स्वरूप देना शुरू किया। आधुनिक मशीनों से बढ़ी गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता ऋण राशि से सरिता ने अपनी इकाई में कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, ऑयल फिल्टर मशीन, मसाला पल्वराइजर मशीन और ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन स्थापित कीं। आधुनिक मशीनों से उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ ही उत्पादों की गुणवत्ता, स्वच्छता और पैकेजिंग में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ। सरिता ने अपने उत्पादों को 'मनोज मसाला एवं ऑयल' के नाम से स्थानीय ब्रांड के रूप में बाजार में उतारा। बेहतर गुणवत्ता और आकर्षक पैकेजिंग से उनके उत्पादों को बाजार में पहचान मिली और धीरे-धीरे कारोबार का दायरा बढ़ने लगा। आठ-दस हजार से बढ़कर 70-80 हजार रुपये हुई मासिक आय व्यवसाय के आधुनिकीकरण का सीधा असर सरिता की आय पर पड़ा। पहले छोटे स्तर पर व्यवसाय से उन्हें लगभग 8 से 10 हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी होती थी। अब सभी व्यावसायिक खर्चों और बैंक ऋण की किश्तों का भुगतान करने के बाद भी वे लगभग 70 से 80 हजार रुपये प्रतिमाह का शुद्ध मुनाफा अर्जित कर रही हैं। सरिता की सफलता केवल उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। व्यवसाय के विस्तार के बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर तीन युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। उनका उद्यम अब उनके परिवार के साथ अन्य परिवारों की आजीविका का भी माध्यम बन गया है। श्रीमती सरिता कुशवाह अपनी सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, जिला प्रशासन भोपाल तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से मिले मार्गदर्शन को देती हैं। उनका कहना है कि शासकीय योजना से मिली वित्तीय सहायता और विभागीय सहयोग ने उनके हुनर को सफल व्यवसाय में बदलने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जा रहा है। सरिता कुशवाह की सफलता इसी संकल्प का जीवंत उदाहरण है।

संपादकीय

तेल पर अमेरिकी दबाव के बीच भारत की दो टूक!

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा रूस और ईरान से संबंधित नए प्रतिबंध कानून को पारित कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों पर सौ प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने के बाद वैश्विक स्तर पर नए समीकरण बन गए हैं। अब दबाव भारत समेत उन तमाम देशों पर आ रहा है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेज खरीदते हैं। एक ओर अमेरिका का संदेश साफ है कि वह ऐसे देशों पर शत-प्रतिशत टैरिफ की मार देगा, दूसरी ओर भारत है, जिसने अमेरिका को संदेश दिया है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता।

वस्तुतः विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा खरीद जारी रखेगा, जिस पर कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम समय-समय पर उठाता रहेगा। एक तरह से देखें तो अमेरिका को यह संदेश देना जरूरी था। फिर रूस से भारत की तेल खरीद कोई आज की बात तो है नहीं, हां, इसमें इतना जरूर हुआ है कि 2022 के बाद तेजी आई है, वह भी इसलिए क्योंकि भारत को अपनी ऊर्जा लागत को नियंत्रित रखना था।

यहां यह भी ध्यान रहे कि भारत ने रूस से तेल खरीदते समय दुनिया के अन्य देशों से ऊर्जा आयात बंद नहीं किया है। भारत की शुरू से नीति ही रही है कि वह किसी एक देश पर निर्भर न रहकर अपनी जरूरत के हिसाब से अधिकतम स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता रहेगा। स्वभाविक तौर पर भारत का तर्क भी यही है कि जब विश्व के कई बाजारों में तेल उपलब्ध है, तब राजनीतिक प्राथमिकताओं के कारण महंगे विकल्प क्यों चुने जाएं?

आज का घटनाक्रम अचानक पैदा नहीं हुआ है। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से भारत पर रूसी तेल की खरीद सीमित करने का दबाव रहता रहा है। 2025 में यह दबाव सीधे टैरिफ तक पहुंच गया था। अगस्त 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले उत्पादों पर रूसी तेल आयात के कारण अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया, फिर जब फरवरी 2026 में अमेरिका ने वही अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटाया तो कहा गया, भारत ने रूसी तेल आयात रोकने की दिशा में कदम उठाने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता व्यक्त की, इसलिए यही शुल्क हटाने का आधार है।

ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को देखने पर एक बात साफ दिखाई देती है कि ऊर्जा खरीद का प्रश्न भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में बातचीत और दबाव, दोनों का हिस्सा बन चुका है, किंतु इस बीच एक अच्छा काम यह हुआ है कि भारत ने अमेरिका को बहुत स्पष्ट संदेश दिया है और वह यही है कि मोदी सरकार आम आदमी की जेब पर तेल का बोझ बिल्कुल नहीं डालेगी। हालांकि तेल के इतर दोनों देश (भारत-अमेरिका) रक्षा, तकनीक, शिक्षा, व्यापार और रणनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। भारत हमेशा से ही अमेरिका के साथ संबंधों को महत्व देता है और अमेरिका भी भारत को हिंद-प्रशांत तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, किंतु जब साझेदार एक देश दूसरे की ऊर्जा नीति निर्धारित करने लगे तब फिर विरोध का ही रास्ता शेष बचता है। बेशक, भारत को अमेरिका के साथ संवाद जारी रखना चाहिए, बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए और जहां संभव हो वहां अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद भी खरीदने चाहिए, किंतु अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रीय हितों को ही ध्यान में रखकर लिए जाएंगे, यही किसी भी बराबरी की साझेदारी की बुनियादी शर्त है।

अमेरिकी कानून का निशाना बड़े देशों में भारत के अलावा चीन पर भी है। चीन ने भी अमेरिकी कदम पर आपत्ति जताई है। बीजिंग ने इसे एकतरफा माना है और कहा है कि यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून में विपरीत है। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम से भारत को एक महत्वपूर्ण सबक लेना चाहिए। यदि कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊर्जा स्रोतों पर दबाव डाल सकती है, तो हमें अपनी ऊर्जा निर्भरता कम करने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना होगा, ताकि जितना संभव हो हम दूसरों पर अपनी निर्भरता कम से कम कर सकें।

योगी आदित्यनाथ पर उनके काम, उपलब्धियों और आंकड़ों के आधार पर हो बात

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

> रोजगार के प्रश्न पर सरकार ने सरकारी नियुक्तियों और निजी क्षेत्र दोनों को समानांतर रूप से आगे बढ़ाने की नीति अपनाई। पिछले वर्षों में 9.30 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी गईं। इसके साथ रोजगार संगम पोर्टल सरकारी और निजी नौकरियों, रोजगार मेलों, कैंपस प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। पोर्टल पर वर्तमान में 45.75 लाख से अधिक नौकरी चाहने वालों का पंजीकरण और 7.60 लाख से अधिक जॉब अवार्ड दर्ज हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में कितनी भी तीखी भाषा इस्तेमाल की जाए, उससे एक बुनियादी तथ्य नहीं बदलता कि किसी सरकार का मूल्यांकन अंततः उसके काम और उसके परिणामों से होता है। वर्ष 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी, तब राज्य के सामने कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, निवेश, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास जैसी अनेक बड़ी चुनौतियां मौजूद थीं।

करीब नौ वर्ष बाद तस्वीर को समझने के लिए राजनीतिक नारों से अधिक महत्वपूर्ण वे आंकड़े हैं, जो सरकार के कामकाज का एक ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति में गोरखपुर और पूर्वांचल की इंसेफेलाइटिस त्रासदी कोई नया मुद्दा नहीं थी। मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वे संसद में इस बीमारी के कारण बच्चों की मौतों का मुद्दा उठाते रहे। सत्ता में आने के बाद इस समस्या से निपटने के लिए स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण विकास को जोड़कर काम किया गया।

वस्तुतः सरकारी आंकड़े इस बदलाव की दिशा को ओर अधिक स्पष्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में 2023 में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के मामलों में 76 प्रतिशत और मृत्यु-दर में 98 प्रतिशत की कमी हुई। जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों में 85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 96 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। यानी जिस बीमारी को पूर्वांचल के हजारों परिवारों की नियति मान लिया गया था, उसके विरुद्ध रोकथाम, स्वच्छता, पेयजल और चिकित्सा व्यवस्था को एक साथ जोड़कर परिणाम हासिल करने का दावा अब आंकड़ों में दर्ज है। आगे स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव इंसेफेलाइटिस तक सीमित न रहते हुए सुधार की दिशा में बहुत आगे पहुंचा। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश आज 63,407 पंजीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ देश में पहले स्थान पर है। राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है, जिनमें से कई नए सरकारी मेडिकल कॉलेज योगी शासन के दौरान ही स्वीकृत और बनाए गए हैं। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 22,681 आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और राज्य में कुल सरकारी अस्पतालों की संख्या 4,942 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.31 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं, जिससे कुल 5.59 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आ चुके हैं। योजना के अंतर्गत करीब 13,353 करोड़ रुपये खर्च करके 81.55 लाख से अधिक मरीजों का अब तक मुफ्त इलाज किया जा चुका है। इलाज को सुगम बनाने के लिए राज्य में आयुष्मान योजना से जुड़े 6,213 अस्पतालों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना भी पूरी तरह काम कर रही है। 74 जिलों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है और सस्ते दामों पर दवाइयाँ देने के लिए 873 जन औषधि केंद्र संचालित हैं। मरीजों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए '108' और '102' सेवाओं के तहत 4,500 से अधिक एंबुलेंस का बेड़ा तैनात है, जिससे अब तक करोड़ों लोग लाभ उठा चुके हैं।

डिजिटल हेल्थ और मातृ स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी राज्य ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रदेश में अब तक 5.76 करोड़ से अधिक नागरिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किए जा चुके हैं। अस्पतालों और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के कारण राज्य में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा सुधरकर 96.12 फीसद तक पहुंच गया है। गर्भवती महिलाओं को इसके तहत मुफ्त अल्ट्रासाउंड के लिए ई-वाउचर की सुविधा भी दी जा रही है।

योगी सरकार की सबसे प्रमुख राजनीतिक पहचान कानून-व्यवस्था को लेकर बनी। सरकार ने अपराध और माफिया के खिलाफ ह्यजीरो टॉलरेंसह्न नीति को शासन का प्रमुख आधार बनाया। अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई, संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान और पुलिस व्यवस्था में तकनीकी बदलाव को इसी नीति से जोड़ा गया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक नीतियों में भी सुरक्षा और निवेश के वातावरण को साथ-साथ रखा जा रहा है।

कभी उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए कठिन राज्य मानने की धारणा रही थी। अब नीतिगत सुधारों और ह्यईज ऑफ डूइंग बिजनेसह्न के जरिए राज्य की निवेश क्षमता बदली है। फरवरी 2026 में सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले करीब नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की बात सामने आई। जिसमें कि 60 लाख से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका तेजी से बढ़ी है। वर्तमान सरकारी पोर्टल पर लगभग 99 लाख एमएसएमई और 98.16 लाख औपचारिकीकृत एमएसएमई दर्ज हैं। इनमें 17.35 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले उद्यम भी दर्ज हैं। ह्यएक जिला, एक उत्पादह्न योजना ने स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारीगरों को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया। यह आंकड़ा उस विकास मॉडल की ओर संकेत करता है जिसमें रोजगार का अर्थ सरकारी नौकरी से इतर उद्यमिता और स्वरोजगार भी है।

योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की विकास नीति में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारों को महत्वपूर्ण स्थान मिला। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को तेज संपर्क से जोड़ने की दिशा में काम किया। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को भी औद्योगिक विस्तार से जोड़ा गया है ।प्रदेश में 1947 से 2017 तक कुल करीब 14 हजार कारखाने थे, जबकि पिछले साढ़े आठ वर्षों में यह संख्या 31 हजार से अधिक हो गई।

भारतवंशी चीतों की बढ़ती संख्या

प्रमोद भार्गव

एक समय था जब चीते की रफ्तार भारतीय वनों की शान हुआ करती थी लेकिन 1947 के आते-आते चीतों की आबादी पूरी तरह लुप्त हो गई। 1948 में अंतिम चीता छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखा गया था। जिसे मार गिराया गया था। चीता तेज रफ्तार का आश्चर्यजनक चमत्कार माना जाता है। अपनी विशिष्ट एवं लोचपूर्ण देयदृष्टि के लिए भी इस हिंसक वन्य जीव की अलग पहचान थी। शरीर में इसी चपलता के कारण यह जंगली प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है। बीती सदी में चीतों की संख्या एक लाख तक थी लेकिन अफ्रीका के खुले घास वाले जंगलों से लेकर भारत सहित लगभग सभी एशियाई देशों में पाया जाने वाला चीता पूरे एशियाई जंगलों में गिनती के रह गए हैं। राजा चीता (एसिनोनिक्स रेक्स) जिम्बाब्वे में मिलता है।

दुर्लभ चीता परियोजना की सफलता अंततः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की देन है। मोदी देश ही नहीं दुनिया के ऐसे विरल सोच वाले नेता हैं, जो एक साथ अनेक विषयों पर सोचने के साथ क्रियान्वयन तो करते ही हैं, प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भी उनके सोच के दायरे में। देश में चीता पुनर्वास परियोजना उनकी इसी दृष्टि का एक सफल कीर्तिमान है। मध्यप्रदेश जिले के श्योपुर जिले में स्थित कूनो आभ्यारण्य की धरती पर अफ्रीका से लाए चीतों का पालन-पोषण चार साल पहले आरंभ हुआ था, जो अब एक बड़े भारतवंशी चीतों के कुल में बदल गया है। अफ्रीका से लाए चीतों के जीवित रहने की दर अनुमान से ज्यादा बेहतर रही। इसी का परिणाम है कि भारत में जन्म लेने वाले चीता शावकों का वंश लगातार बढ़ रहा है। कूनो में जन्मी मादा चीताएं अनेक बार मां बन चुकी हैं। इनसे जन्मे 19 शावक पूरी तरह स्वास्थ्य रहते हुए जंगली बाड़े में नटखट अठखेलियां करते हुए देखे जा सकते हैं। मानवीय निगरानी के बीच इनकी वृद्धि शत-प्रतिशत आंकी गई है। मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2022 को कूनो में नमीबियाई चीतों को छोड़ने के साथ इनके पुनर्वास की पहल हुई थी। वर्तमान में यहां चार मादाओं के 19 शावक उछलकूद मचाए हुए हैं।

भारत की धरती पर अब तक 49 चीतों का जन्म हो चुका है, जिनमें से 32 जीवित हैं। यानी कूनो में चीतों के जीवित रहने की दर 65.3 प्रतिशत है, जबकि इनके मूल निवास स्थल अफ्रीकी जंगलों में प्राकृतिक रूप से महज 5 से 10 प्रतिशत शावक ही व्यस्क होने का सुख भोग पाते हैं। यहां ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वनकर्मी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से कर रहे हैं। दरअसल, कूनो का प्रबंधन बाहरी हस्तक्षेप से लगभग मुक्त है। इसीलिए यह वन प्रांत अफ्रीकी देशों से लाए गए चीतों के वंश के महाद्वीप में बदलता जा रहा है। यहां के वातावरण से अफ्रीका के वातावरण को भिन्न एवं प्रतिकूल माना जा रहा था, किंतु अब चीतों की संख्या में वृद्धि ने जता दिया है कि कूनो के जंगल का परिवेश इन चीतों के रहवास हेतु अनुकूलन रच रहा है। यह प्रकृति की ही देन हैं। प्रदेश के जंगलों में बाघ, तेंदुए और स्याहगोश तो पूर्व से ही हैं, अब बिल्ली प्रजाति का चीता भी यहां के आभ्यारण्यों में देखा जाने लगा है। प्रदेश के ही गांधी सागर आभ्यारण्य में भी चीते छोड़े गए हैं लेकिन यहां इनकी फिलहाल वंशवृद्धि शुरू नहीं हुई है। हालांकि चीता शावकों के जन्म को लेकर यह विडंबना देखने में आ रही है कि जो चीते बाड़े में जन्म लेते हैं, उनके जीवित रहने की दर तो उत्तम है, किंतु खुले जंगल में जन्मे ज्यादातर चीते जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। कूनो में जन्मी मादा केजीपी-12 ने 11 अप्रैल 2026 को खुले जंगल में चार शावकों को जन्म देकर इतिहास रचा था। यह भारत में जन्मी किसी मादा द्वारा वन में प्राकृतिक प्रसव का पहला मामला था लेकिन एक महीने के भीतर 12 मई को चारों शावक मृत पाए गए। इसके बाद छह जून को इनकी मां का भी निधन हो गया। ये मौतें कैसे हुईं, यह रहस्य ही बना हुआ है।

नमीबिया से लाए गए आठ चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री ने छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते और लाकर छोड़े गए थे। नई धरती और जलवायु परिवर्तन के चलते इन चीतों को आरंभ में यहां के मौसम से तालमेल बिठाने में दिक्कतें आईं। नतीजतन छह वयस्क और यहीं पैदा हुए चार शावकों में से तीन की मौतें भी हुईं थीं, इस कारण परियोजना पर सवाल भी खड़े किए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से लाकर बसाए गए 12 चीतों को 18 फरवरी 2024 को दो साल पूरे हो हुए थे, इस अवधि में इन चीतों की मृत्यु दर में कमी ने परियोजना की सफलता के प्रथम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इनकी जीवित रहने की दर शुरूआत में नमीबिया से लाए चीतों से बेहतर रही थी। दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों में से 33.3 प्रतिशत की मौत हुई, जबकि नमीबिया से लाए गए चीतों में से 37.5 प्रतिशत चीतों की मौत हुई। अफ्रीका से लाई गई तीन मादा चीताओं ने अब तक 12 शावकों को जन्म दिया, जो भारतीय परिवेश में पलते एवं बढ़ते चले गए। इन्होंने ही नए घर कूनो में आबादी बढ़ाने की शुरूआत की थी। नए आवास स्थलों में 50 फीसदी चीतों की मौत को सामान्य माना जाता है।

एक समय था जब चीते की रफ्तार भारतीय वनों की शान हुआ करती थी लेकिन 1947 के आते-आते चीतों की आबादी पूरी तरह लुप्त हो गई। 1948 में अंतिम चीता छत्तीसगढ़ के सरगुजा में देखा गया था। जिसे मार गिराया गया था। चीता तेज रफ्तार का आश्चर्यजनक चमत्कार माना जाता है। अपनी विशिष्ट एवं लोचपूर्ण देयदृष्टि के लिए भी इस हिंसक वन्य जीव की अलग पहचान थी। शरीर में इसी चपलता के कारण यह जंगली प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है। बीती सदी में चीतों की संख्या एक लाख तक थी लेकिन अफ्रीका के खुले घास वाले जंगलों से लेकर भारत सहित लगभग सभी एशियाई देशों में पाया जाने वाला चीता पूरे एशियाई जंगलों में गिनती के रह गए हैं। राजा चीता (एसिनोनिक्स रेक्स) जिम्बाब्वे में मिलता है। अफ्रीका के जंगलों में भी गिने-चुने चीते रह गए हैं। तंजानिया के सेरेंगती राष्ट्रीय उद्यान और नमीबिया के जंगलों में गिने-चुने चीते हैं। प्रजनन के तमाम आधुनिक व वैज्ञानिक उपायों के बावजूद जंगल की इस फुतीर्ली नस्ल की संख्या बढ़ाई नहीं जा पा रही थी। यह प्रकृति के समक्ष वैज्ञानिक दंभ की नाकामी मानी जाने लगी थी। जूलॉजिकल सोसायटी आफ लंदन की रिपोर्ट को मानें तो दुनिया में 91 प्रतिशत चीते 1991 में ही समाप्त हो गए थे। एशिया में ईरान में केवल 50 चीते शेष हैं। अफ्रीकी देश केन्या के मासीमारा क्शेत्र को चीतों का गढ़ माना जाता था लेकिन अब इनकी संख्या गिनती की रह गई है। ऐसे में भारत में चीतों की वंशवृद्धि दुनिया के लिए खुशखबरी है।

बीती सदी के पांचवें दशक तक चीते अमरीका के चिड़ियाघरों में भी थे। प्राणी विशेषज्ञों की अनेक कोशिशों के बाद इन चीतों ने 1956 में शिशुओं को जन्म भी दिया, परंतु किसी भी शिशु को बचाया नहीं जा सका। चीते द्वारा किसी चिड़ियाघर में जोड़ा बनाने की यह पहली घटना थी, जो नाकाम रही। जंगल के हिंसक जीवों का प्रजनन चिड़ियाघरों में आश्चर्यजनक ढंग से प्रभावित होता है इसलिए शेर, बाघ, तेंदुए व चीते चिड़ियाघरों में जोड़ा बनाने की इच्छा नहीं रखते हैं। भारत में चीतों की अंतिम पीढ़ी के कुछ सदस्य बस्तर-सरगुजा के घने जंगलों में थे, जिन्हें 1947 में देखा गया था। प्रदेश अथवा भारत सरकार इनके संरक्षण के जरूरी उपाय करने हेतु हरकत में आती, इससे पहले ही चीतों के इन अंतिम वंशजों को भी शिकार के शौकीन राजा-महाराजाओं ने मार गिराया और भारतीय चीतों की नस्ल पर पूर्ण विराम लग गया था। कूनो के बाद अब मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गांधीसागर अभ्यारण्य में चीते छोड़े गए हैं। यहां भी कूनो की तरह इनकी वंशवृद्धि की उम्मीद है। हमारे देश के राजा-महाराजाओं को घोड़ों और कुत्तों की तरह चीते पालने का भी शौक था। चीता शावकों को पालकर इनसे जंगल में शिकार कराया जाता था। राजा लोग जब जंगल में आखेट के लिए जाते थे, तो प्रशिक्षित चीतों को बैलगाड़ी में बिठाकर साथ ले जाते थे। इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी, जिससे यह किसी मामूली वन्य जीव पर न झपटे। जब शिकार राजाओं की दृष्टि के दायरे में आ जाता था, तो चीते की आंखों की पट्टी खोलकर शिकार की दिशा में हाथ से इशारा कर दिया जाता था। पलक झपकते शिकार चीते के जबड़े में होता।

न्यूज ब्रीफ

पुलिस ने वाहन चोर को गिरफ्तार कर मोटर सायकिल की जप्त

ग्वालियर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह(भापुसे) के निर्देश पर ग्वालियर जिले में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर वाहन चोरों की धरपकड़ हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य अति0 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री जयराज कुबेर द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में चोरी गये वाहनों की बरामदगी कर चोरों को पकड़ने हेतु मुखबिर तंत्र विकसित करने के निर्देष दिये गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के परिपालन में एसडीओपी भितरवार श्री गगन हनवत के कुषल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भितरवार उनि0 बलवीर मावई के द्वारा थाना बल की टीम को थाना के अप0क्र0-367/26 धारा 303(2) बीएनएस के प्रकरण में चोरी गई हीरो एचएफ डीलक्स मोटर सायकिल को बरामद कर चोर को पकड़ने हेतु लगाया गया। दौराने विवेचना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर से उक्त प्रकरण में संदेही व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

शहर स्वच्छ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों से वसूला जुर्माना

ग्वालियर। शहर स्वच्छ व साफ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने वालों एवं भवन सामग्री सडक पर डालने वालों पर निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी एवं अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। पमनानी के निर्देशन में क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 8 में सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने, प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग, विक्रय करने तथा गोबर निष्कासन के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए व्यक्तियों एवं व्यापारियों से 10,850 का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान के निर्देशन में जोन 20 वार्ड क्रमांक 53 में मुख मार्ग पर कचरा फेंकने पर संबंधित व्यक्ति को रोका टोका एवं 500 का जुर्माना भी किया गया।

मां सरस्वती एवं गणेश जी की पूजा अर्चना के बाद लिखना शुरू किया था रामचरित्र मानस

ग्वालियर। खाटू श्याम मंदिर राधा की हवेली बाई साहब की परेड लक्ष्मीगंज स्थित पर चल रहे 15वे वार्षिक महोत्सव के दौरान 18 सितंबर से राम कथा का आयोजन पंडित संजीव कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से हुआ कथा के पहले दिन बताया गया राम नाम अति मीठा है कोई बुलाकर देख ले साथ ही काम क्रोध लाभ जहां भी यह रहते हैं वहां प्रभु नहीं रहते कथा कहते हुए उन्होंने बताया पक्षीराज गरुड़ जी ने काकभुशुण्डि जी (जिन्हें कई कल्पों तक जीवित रहने और रामकथा के परम ज्ञाता होने के कारण आदर से जाना जाता है) से रामकथा सुनाने के लिए विनयपूर्वक निवेदन किया था।जब गरुड़ जी के मन में भगवान श्री राम के चरित्र और उनकी लीलाओं को देखकर कुछ संशय (मोह) उत्पन्न हो गया था, तब भगवान शिव के निर्देश पर वे अपने संशय को दूर करने के लिए नील पर्वत पर काकभुशुण्डि जी के पास पहुंचे। वहाँ गरुड़ जी ने उनसे प्रार्थना की।

`मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' का आयोजन लगातार किया जा रहा

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर में मौके पर सुलझीं 36 से अधिक समस्याएं

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप आम जनों को शासकीय योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 9 माल रोड मुरार पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें आमजन से जुडी हुई 36 समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। षिविर में क्षेत्राधिकारी श्रीमती प्रगति गोस्वामी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर के दौरान सैकड़ों की संख्या में अन्य विभागीय व नागरिक सुविधाओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए, जिन्हें दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को समयसीमा के भीतर निराकृत करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान नगर निगम के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आगामी शुक्रवार को यहां पर लगेगा शिविर मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अगला शिविर दिनांक 25 सितम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 17 ढोली बुआ का पुल, 9 अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 10 (जिला स्तरीय शिविर), दिनांक 16 अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 03 एवं 14, दिनांक 23 अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 10 एवं 24, दिनांक 30 अक्टूबर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 07 एवं 22, दिनांक 6 नवम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 04 एवं 20, दिनांक 13 नवम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 11 एवं 21, दिनांक 20 नवम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 18 एवं 25, दिनांक 27 नवम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 23, दिनांक 04 दिसम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 05, दिनांक 12 दिसम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 12, दिनांक 18 दिसम्बर को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 19, दिनांक 01 जनवरी 2027 को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 01 एवं दिनांक 8 जनवरी 2027 को क्षेत्रीय कार्यालय क्रमांक 13 पर षिविर आयोजित किए जाएगें।

हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, श्रमिक को मिलेंगे 6.44 लाख रुपये

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने श्रम कानूनों और कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कृषि उपज मंडी समिति को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मंडी समिति की रिट अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को पूरी तरह से बरकरार रखा है। इस कानूनी प्रक्रिया के तहत अब मंडी समिति को संबंधित श्रमिक को 6 लाख 44 हजार 137 रुपए की राशि का भुगतान करना होगा।

यह पूरा कानूनी विवाद श्रमिक राकेश सक्सेना की बहाली और बकाया वेतन से जुड़ा हुआ है। श्रम न्यायालय क्रमांक-1, ग्वालियर ने एक फरवरी 2003 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें राकेश सक्सेना को बिना पिछले वेतन के दोबारा सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए गए थे। श्रम न्यायालय का यह आदेश लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान हाई कोर्ट तक पहुंचा और हर चरण में बरकरार रखा गया। अदालत के स्पष्ट निर्देश और आदेश होने के बावजूद कृषि उपज मंडी समिति ने श्रमिक को समय पर सेवा में वापस नहीं लिया, जिसके चलते वे बिना बहाली के ही 31 अगस्त 2007 को सेवानिवृत्त (रिटायर) हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद श्रमिक राकेश सक्सेना ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी(2) के तहत श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बहाली के मूल आदेश की तिथि से लेकर अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक के वेतन और एरियर की मांग करते हुए अपनी पूरी गणना (कैलकुलेशन) श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की।

सीवर सफाई के लिए ग्वालियर की गलियों का सर्वे, जगह के हिसाब से चुनी जाएगी मशीन

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लगातार बनी सीवर और ओवरफ्लो की समस्या से निपटने के लिए अब नगर निगम ने एक ठोस और व्यावहारिक कार्ययोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। शहर की हर गली और मोहल्ले में सीवर सफाई सुगम बनाने के लिए अब गलियों की चौड़ाई के आधार पर आधुनिक मशीनों की जरूरत तय की जाएगी। इसके लिए विशेष रूप से शहर की गलियों का व्यापक सर्वे कराया जाएगा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी ने हाल ही में शहर के वार्ड 17 और 18 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल नगर पहुंचकर सीवर सफाई के लिए उपयोग में लाई जाने वाली आधुनिक मशीनों का विशेष प्रेजेंटेशन देखा। मौके पर सीवर सक्शन कम जेटिंग मशीन, डी-सिल्टिंग मशीन और डी-सिल्टिंग कम जेटिंग मशीन मंगाई गई थीं। निगमायुक्त ने इन सभी मशीनों की कार्यक्षमता को परखा और मौके पर ही सीवर लाइन खुलवाकर सफाई प्रक्रिया का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर की प्रत्येक गली की चौड़ाई का सर्वे कराया जाए। जिन क्षेत्रों में सीवर चोक होने और ओवरफ्लो की समस्या सबसे अधिक है, वहां प्राथमिकता के आधार पर सर्वे किया यह देखा जाए कि किस चौड़ाई की गली में कौन सी मशीन आसानी से प्रवेश कर सकती है और प्रभावी ढंग से काम कर सकती है।

हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे 05 जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह,भापुसे के निर्देष पर ग्वालियर जिले में जुआरियों व सटोरियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में दिनांक 17.09.2026 को थाना जनकगंज पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में मेहरा साहब की तलैया वाली दरगाह के पास लक्ष्मीगंज में कुछ युवक हार जीत का दाव लगाकर ताश पत्ते से जुआ खेल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषों के परिपालन में सीएसपी लष्कर श्रीमती किरण अहिरवार के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी जनकगंज निरीक्षक अतुल सिंह सोलंकी के द्वारा पुलिस की टीम को मुखबिर सूचना की तस्दीक कर कार्यवाही करने हेतु भेजा गया। पुलिस टीम मुखबिर के बताये स्थान मेहरा साहब की तलैया वाली दरगाह के पास लक्ष्मीगंज में कुछ युवक हार जीत का दाव लगाकर रूपयों से ताश के पत्तों से जुआ खेलते हुए दिखाई दिये। पुलिस टीम द्वारा घेरकर जुआरियों को पकड़ा और उनका नाम पता पूछा तो अपने नाम क्रमषः (1) नीरज चौरसिया पुत्र पुरुषोत्तम चौरसिया उम्र 25 साल निवासी जनकपुरी ग्वालियर (2) संजय मुदगल पुत्र बसंत मुदगल उम्र 25 साल निवासी गोकुलपुर गिरवाई ग्वालियर (3) शेखर चौरसिया पुत्र पुरुषोत्तम चौरसिया उम्र 19 साल निवासी जनकपुरी गोलपहाडिया ग्वालियर (4) रवि चौरसिया पुत्र राजू चौरसिया उम्र 25 साल निवासी जनकपुरी ग्वालियर (5) लक्ष्मण जाट पुत्र सुरेन्द्र सिंह उम्र 37 साल निवासी संजय नगर लक्ष्मीगंज ग्वालियर बताये। पुलिस द्वारा आरोपीगण के कब्जे से 52 ताश के पत्ते की एक गड्डी तथा कुल नगदी 8520/- रुपए नगद जप्त किये गये।

हाइवे पर बेहतर रोशनी के साथ निगरानी व्यवस्था को किया जाएगा और मजबूत

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश में अब नेशनल हाइवे और एक्सप्रेस-वे की सूरत बदलने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशों के पालन में प्रदेश के प्रमुख शहरों–ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, हरदा, खंडवा, रीवा, रतलाम, सागर, उज्जैन और विदिशा से गुजरने वाले नेशनल हाइवे पर नया और आधुनिक केंद्रीयकृत स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इस कदम से हाइवे पर रात के समय सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था और अधिक बेहतर हो जाएगी। पारंपरिक व्यवस्था में स्ट्रीट लाइटें आमतौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के हिसाब से ही बंद या चालू होती हैं। इसके अलावा, लाइट खराब होने की जानकारी तब मिल पाती थी जब पेट्रोलिंग वाहन वहां से गुजरते थे। लेकिन इस नई तकनीक के आने से पूरी व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगीः अब इन स्ट्रीट लाइटों को रिमोट के माध्यम से आसानी से बंद और चालू किया जा सकेगा। प्रत्येक लाइट केंद्रीय नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली के दायरे में रहेगी। जैसे ही कोई स्ट्रीट लाइट बंद या खराब होगी, उसकी जानकारी तुरंत कंट्रोल रूम के पैनल पर दिखने लगेगी। वेब-आधारित केंद्रीय सर्वर सभी कॉरिडोर की लाइटों का डेटा सुरक्षित रखेगा और मैप पर हर एक लाइट की लाइव लोकेशन व स्थिति देखी जा सकेगी।

औचक निरीक्षण कर जब्त किए 16 घरेलू गैस सिलेंडर

अवैध रूप से भंडारित गैस सिलेंडरों के मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

जिले में रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिये कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को ग्राम बेरजा, जनपद पंचायत मुरार स्थित विनायक गैस रिपेयरिंग दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान परिसर से बड़ी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडर अनधिकृत रूप से भंडारित पाए गए। निरीक्षण के दौरान ग्राम बेरजा स्थित जितेन्द्र पाल की दुकान से बीपीसीएल कंपनी के 13 भरे हुए 14.2 किलोग्राम क्षमता के घरेलू गैस सिलेंडर, बीपीसीएल कंपनी के 2 खाली 14.2 किलोग्राम क्षमता के सिलेंडर तथा एचपीसीएल कंपनी का 1 खाली 14.2 किलोग्राम क्षमता का सिलेंडर मिला। इस प्रकार कुल 16 घरेलू गैस सिलेंडर मौके पर अनधिकृत रूप से भंडारित पाए गए। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि इन सिलेंडरों को जितेन्द्र पाल के आधिपत्य से जब्त कर राजा गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में यथास्थिति रखे जाने के लिए दिया है। अनियमितता पाए जाने पर जितेन्द्र पाल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण तैयार कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई में जिला आपूर्ति नियंत्रक अरविन्द सिंह भदौरिया, सहायक आपूर्ति अधिकारी महावीर सिंह राठौर एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी संजीव शर्मा शामिल रहे।

ऑपरेटरों को नहीं मना सके अधिकारी, 512 रूटों पर स्कूली बस सेवा बंद

ग्वालियर-चंबल अंचल समेत पूरे एमपी में बस सेवा शुरू नहीं, ग्रामीण बच्चों की बढ़ी मुश्किलें

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत शुरू किए गए सांदीपनि स्कूलों में विद्यार्थियों के आवागमन के लिए वाहन सेवा का गंभीर संकट बना हुआ है। स्कूल शुरू हुए ढाई महीने से अधिक का लंबा समय बीत चुका है, लेकिन ग्वालियर-चंबल अंचल सहित प्रदेश के कई जिलों में विद्यार्थियों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए अभी तक बस सेवा शुरू नहीं हो सकी है। बस ऑपरेटरों को राजी करने में नाकाम अधिकारी हाल ही में आयुक्त लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे जिला स्तर पर ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं और स्थानीय बस ऑपरेटरों के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द बसों का संचालन शुरू करवाएं। इसके बावजूद, स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी बस ऑपरेटरों को राजी करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसका खमियाजा छात्र-छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। 512 रूटों पर चलना है स्कूल बसों को स्थिति की गंभीरता को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है: ग्वालियर शिक्षा संभाग के जिलेः इस संभाग के अंतर्गत कुल आठ जिले आते हैं। सांदीपनि स्कूलों की संख्याः इनमें ग्वालियर में 8, मुरैना में 8, भिंड में 7, शिवपुरी में 8, श्योपुर में 3, दतिया में 4, गुना में 6 और अशोकनगर में 3 सांदीपनि स्कूल संचालित हो रहे हैं। प्रभावित रूटः इन सभी स्कूलों के बच्चों को लाने और ले जाने के लिए कुल 512 रूट तय किए गए हैं, जिन पर स्कूल बसों का संचालन किया जाना है, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती के कारण यह योजना पटरी पर नहीं आ पा रही है। वाहनों की उचित व्यवस्था न होने से सबसे बड़ी और गंभीर परेशानी ग्रामीण अंचल के छोटे-छोटे बच्चों के सामने खड़ी हो गई है। दरअसल, शिक्षा विभाग ने सांदीपनि स्कूलों के 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम छोटे प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों को इनमें मर्ज कर दिया है। पुराने और स्थानीय स्कूलों के बंद हो जाने के बाद अब 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित गांवों में रहने वाले नौनिहालों के सामने रोजाना स्कूल पहुंचने की बड़ी चुनौती बन गई है। गरीब और किसान परिवारों के लिए रोज निजी वाहनों या ऑटो का खर्च उठाना आर्थिक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

सीरीज वेटिंग है का ट्रेलर जारी, पुलिस वाले के किरदार में दिखेंगे दिव्येंदु

फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' से दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद, अभिनेता दिव्येंदु अब अपकमिंग सीरीज 'वेटिंग है' में रेलवे कॉन्स्टेबल का रोल निभाने के लिए तैयार हैं। मेकर्स ने इस स्कैम-बेस्ड कॉमेडी-ड्रामा का ट्रेलर जारी किया है।

'वेटिंग है' सीरीज के ट्रेलर में कन्फर्म रेलवे टिकट पाने के आम संघर्ष पर आधारित कहानी की झलक दिखाई गई है। पटना में सेट इस सीरीज की कहानी सुगम मिश्रा (दिव्येंदु) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो रेलवे कॉन्स्टेबल के तौर पर अपनी नई नौकरी में जमने की कोशिश कर रहा है। कहानी में मोड़ तब आता है जब वह देखता है कि बुकिंग विंडो खुलने के कुछ ही सेकंड में रेलवे टिकट कन्फर्म हो जाते हैं। सुगम मामले की जांच शुरू करता है और जल्द ही अफरोज हम्सा (भुवन अरोड़ा) का पीछा करने लगता है।

अफरोज एक टेक एक्सपर्ट है, जिसने टिकट बुकिंग सिस्टम का तोड़ निकाल लिया है। जो मामला शुरू में आसान लगता है, वह जल्द ही एक बड़े रैकेट में बदल जाता है। सुगम की पत्नी प्रिंसी (हर्षिता गौर) भी उसे मामले की गहराई से जांच करने के लिए कहती है। जैसे-जैसे सुगम सच्चाई के करीब पहुंचता है, अफरोज उससे आगे रहने की कोशिश करता है।

परिवार और नौकरी के बीच तालमेल सीरीज के ट्रेलर में सुगम और उनकी पत्नी के बीच संघर्ष भी दिखता है। सुगम अपने परिवार और अपनी नौकरी के बीच तालमेल बिठाते हुए नजर आते हैं। सीरीज में कॉमेडी का डोज भी है।

क्या बोले दिव्येंदु

अपकमिंग सीरीज को लेकर दिव्येंदु ने कहा, 'सुगम की जिस बात ने मुझे आकर्षित किया, वह यह है कि वह कोई आम पुलिस वाला नहीं है जिसे सब कुछ पता हो। वह प्रोफेशनल तौर पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपनी पर्सनल और नई शादीशुदा जिंदगी की सच्चाइयों का भी सामना कर रहा है। यह बैलेंस उसे बहुत रिलेटेबल बनाता है। मुझे उसके इस पहलू को एक्सप्लोर करने में मजा आया।'

दिवाली पर आ हो सकती है नयनतारा की 'मूकुथी अम्मन 2'

नयनतारा एक बार फिर देवी के किरदार में नजर आने के लिए तैयार हैं। उनकी चर्चित फिल्म 'मूकुथी अम्मन' का दूसरा पार्ट यानी 'मूकुथी अम्मन 2' इन दिनों चर्चा में है। इस बार फिल्म का निर्देशन सुंदर सी कर रहे हैं। अब इस की रिलीज को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक... 'निर्माता 'मूकुथी अम्मन 2' को दिवाली के मौके पर थिएटर्स में रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, अभी मेकर्स की ओर से रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई है। फिल्म में रेजिना कैसेंड्रा, अभिनया, योगी बाबू और उर्वशी जैसे कलाकार शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म में कन्नड़ एक्टर विजय की मौजूदगी भी बताई गई है। बता दें कि 'मूकुथी अम्मन 2' का आधिकारिक रूप से ऐलान 2024 में किया गया था। इसके बाद चेन्नई में फिल्म की मुहुर्त पूजा और शूटिंग से जुड़ा काम 2025 में शुरू हुआ हुआ और दिसंबर 2025 तक शूटिंग पूरी भी कर ली गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में इसका बजट करीब 100 करोड़ रुपए बताया गया है।

बतौर निर्माता 'डोंट बी शाय' को लेकर नर्वस महसूस कर रहीं आलिया भट्ट

अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपनी प्रोड्यूस आगामी फिल्म 'डोंट बी शाई' को लेकर सुर्खियों में चल रही हैं। अभिनेत्री ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान बताया कि वह फिल्म के साथ चार नए एक्टर्स और एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने को लेकर ज्यादा नर्वस हैं। ट्रेलर लॉन्च के दौरान आलिया से पूछा गया था कि क्या उन्हें कभी लगा कि उन्हें भी इस फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए थी, तो इस पर उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे इस फिल्म में एक्टिंग करनी चाहिए थी।' आलिया ने फिल्म को लेकर उत्सुकता जाहिर करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करने से उन्हें एक अलग तरह की खुशी मिली है, क्योंकि वह शुरू से ही इसकी कहानी और इसकी दुनिया बनाने में शामिल रही हैं। उन्होंने कहा, '14 साल पहले मैंने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से एक एक्टर के तौर पर अपना डेब्यू किया था और अब इतने सालों बाद मैं चार नए एक्टर्स और एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रही हूं और मैं अभी उनसे कहीं ज्यादा नर्वस हूं। क्योंकि, आपके सवाल का जवाब दूं तो, मुझे एक एक्टर होना और कैमरे के सामने रहना पसंद है, लेकिन एक प्रोड्यूसर होने का एक अलग ही तरह का सुकून है।' एक्ट्रेस ने आगे कहा: 'जब फिल्म की निर्देशक श्रीति मुखर्जी हमारे पास इस मूवी बनाने का आइडिया लेकर आईं, तो हमने ही कहा कि चलो इसे साथ में करते हैं और फिर हम इसे अपने प्यारे पार्टनर्स के पास ले गए। यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और हर कोई इससे जुड़ पाएगा।'

श्रीति मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म 'डोंट बी शाय' 20 साल की लड़की श्यामिली 'शाइ' दास की कहानी है, जो मानती है कि उसने जिंदगी को समझ लिया है, लेकिन वह देखती है कि उसकी सोची-समझी जिंदगी एक अचानक मोड़ ले लेती है, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। इसमें आरुषि बजाज, पीयूष खाती, बियांका अरोड़ा और अंश दुग्गल जैसे नए चेहरे मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ कुणाल रॉय कपूर और नेहा धूपिया भी नजर आएंगे। 25 सितंबर 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है।

फ्रेंच-इंडियन रोमांस 'स्टे' में नजर आएंगी पल्लवी शारदा

अभिनेत्री पल्लवी शारदा जल्द ही फ्रेंच-इंडियन रोमांस फिल्म 'स्टे' में नजर आएंगी। अभिनेत्री का कहना है कि सिनेमा दुनिया का एक ऐसा अजूबा है, जो कैमरा बंद होने के बाद भी एक्टर्स को क्रिएशन के भंवर में खींच लेता है। पल्लवी ने इंस्टाग्राम पर पब्लिकेशन की तरफ से गई अनाउमेंट को शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस फिल्म में सायली नाम की एक तलाकशुदा महिला के किरदार में नजर आएंगी, जो भारत में रहती है और जिसे अपने पिता की सफल कंपनी को संभालने के लिए तैयार किया गया है। पेरिस की एक ट्रिप के दौरान उसे लियो से प्यार हो जाता है, जो एक डिलीवरी ड्राइवर है और एक्टर बनने का सपना देखता है। उनके रिश्ते की परीक्षा परिवार के दबाब, क्लास के फर्क और फ्रांस-भारत में उनकी जिंदगियों को अलग करने वाली आर्थिक और सांस्कृतिक हकीकतों से होती है।

अभिनेत्री फिल्ममेकर रोहेना गेरा के साथ अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए लिखा, 'आप फिल्म बनाते और बेचते हैं। यही तरीका है, लेकिन किसी भी फिल्म के मूल में एक आइडिया, एहसास, वाइब्रेशन होता है। हम बस उसे जिंदा करने में मदद करते हैं। इस फिल्म से पहले जब भी मुझे रोहेना के साथ जूम पर बात करने का मौका मिला, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि हमने एक महिला के तौर पर अपने एहसासों और हमारे आसपास की कहानियों पर गहराई से बात की, जो अलग-अलग देशों और संस्कृतियों में काम कर रही हैं।' उन्होंने लिखा, 'लगातार दो संस्कृतियों के बीच झूलने की अजीबोगरीब स्थिति को समझने की कोशिश की। फिल्में एक अजीब दुनिया हैं। ये आपको क्रिएशन के भंवर में खींच लेती हैं, जिसका एहसास कैमरा बंद होने के बाद भी उतना ही रहता है। सेट के बीच के ठहराव में कभी-कभी खालीपन, बेचैनी महसूस होती है लेकिन साथ ही सब कुछ जुड़ता भी है। एक एक्टर के लिए हर फिल्म का अनुभव आपको अपने अंदर इतना गहरा ले जाता है कि उसे समझने के लिए बीच में ठहराव की जरूरत होती है। मैं अभी भी इस फिल्म को समझ रही हूं।'

'कंगुवा' फेम शिवा के साथ फिल्म करेंगे धनुष

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार धनुष इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर लगातार चर्चा में हैं। एक्टर के पास एक के बाद एक कई बड़े प्रोजेक्ट हैं। अब उनकी फिल्मों की लिस्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ने की चर्चा है। खबरों के मुताबिक... 'धनुष जल्द ही फिल्ममेकर शिवा के साथ काम कर सकते हैं। शिवा वही निर्देशक हैं, जिन्होंने सूर्या स्टारर फिल्म 'कंगुवा' का निर्देशन किया था। अगर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है तो धनुष और शिवा पहली बार किसी फिल्म के लिए साथ काम करेंगे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि धनुष और शिवा की फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर में शुरू हो सकती है।

जीतने के बाद भी क्यों खतरों के खिलाड़ी 15 से बाहर हुए गौरव खन्ना

रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' को अभिनेता गौरव खन्ना ने अलविदा कह दिया है। शो में आखिरी एलिमिनेशन स्टंट में तीन प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें रूहानिका धवन और रुबीना दिलाइक और गौरव शामिल थे। इसके बाद शो में एक जबरदस्त टर्न आया। शो में तीन प्रतिभागी रूहानिका धवन और रुबीना दिलैक और गौरव खन्ना एलिमिनेशन तक पहुंच गए थे। मगर फिर गौरव उस राउंड को जीत लिया था। मगर उन्होंने बीच में ही शो छोड़ने का निर्णय कर लिया। उन्होंने रोहित से 'खतरों के खिलाड़ी 15' से बाहर होने की इजाजत मांगी। यह सब सुनकर शो के होस्ट रोहित समेत सभी प्रतिभागी शॉक्ड हो गए। मगर फिर प्रतिभागियों ने उनका हौंसला बढ़ाया और गौरव ने स्टंट किया।

शो में बोले गौरव

शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में इस स्टंट राउंड को जीतने के बाद गौरव ने कहा, 'भले ही मैंने इसे जीत लिया है, फिर भी मैं शो से बाहर निकलना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। और मैं अब आपको इस तरह से निराश नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि इस शो में स्टंट का स्तर बिल्कुल अलग है।

हैल्थ पर बोले एक्टर

गौरव खन्ना ने हेल्थ अपडेट पर कहा, 'सबसे पहले, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने जानबूझकर यह नहीं कहा कि मैं इस स्टंट को रद्द करना चाहती हूं। मुझे बाद में पता चला कि रूहानिका ने भी इसे रद्द करने की इच्छा जताई थी। और अगर मैं शारीरिक रूप से 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति की जगह नहीं लेना चाहता जो 100 प्रतिशत तैयार हो।'

200 से ज्यादा फिल्मों की स्क्रिप्ट और ब्लैंक चैक!

नवाजुद्दीन ने बताया क्यों ठुकराए बड़े ऑफर

नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज बॉलीवुड के सबसे बड़े कलाकारों में गिने जाते हैं। पहले फिल्मों में छोटे-मोटे रोल निभाने वाले अभिनेता ने कई फिल्मों में लीड रोल किया है। उन्होंने वर्षों तक छोटे-मोटे रोल किए और ऐसे रोल का इंतजार किया जो उनके करियर की दिशा बदल सके। यह टर्निंग पॉइंट 2012 में फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' से आया। इसमें फैजल खान के उनके किरदार ने उन्हें इंडस्ट्री में एक खास पहचान दिलाई। अब पीछे मुड़कर देखते हुए, एक्टर ने फिल्म के रिलीज होने के बाद आए बड़े बदलाव और अचानक मिले ढेर सारे ऑफर को कैसे संभाला, इस बारे में बात की है।

आई थी स्क्रिप्ट की बाढ़

नवाजुद्दीन से पूछा गया कि किस फिल्म ने उन्हें पहली बार स्टार जैसा महसूस कराया। उन्होंने तुरंत 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' का नाम लिया और एनडीटी के साथ बातचीत में कहा 'बेशक, यह 'गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' ही है।' उन्होंने याद किया कि फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स की वजह से उनके पास स्क्रिप्ट्स की बाढ़ आ गई थी।

फैसलों को हावी नहीं होने दिया

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, ''गैंग्स ऑफ वासेपुर 2' के रिलीज होने के बाद, मुझे कम से कम 200 स्क्रिप्ट्स मिलीं। मेरी टेबल पर ब्लैंक चेक रखे होते थे। लोग कहते थे, 'ये रही स्क्रिप्ट और ये रहा ब्लैंक चेक। आप जो चाहें वो रकम लिख दें और जो भी तारीखें आपके पास हों, हमें दे दें।'' एक ऐसे अभिनेता के लिए जिसने वर्षों तक काम की तलाश में बिताए हों, यह स्थिति एक के बाद एक प्रोजेक्ट साइन करने का मौका हो सकती थी। हालांकि, नवाजुद्दीन ने अचानक मिली इस लोकप्रियता को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया।

क्यों ठुकराए ऑफर

सैकड़ों स्क्रिप्ट्स पर विचार करने और अपनी फीस खुद तय करने की आजादी मिलने के बावजूद, उन्होंने उन सभी को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें कहानी या कंटेंट पसंद नहीं आया। अभिनेता ने कहा, 'मैंने उनमें से एक भी स्क्रिप्ट नहीं चुनी क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। मैंने तय किया कि मैं सही स्क्रिप्ट का इंतजार करूंगा।'

नहीं करना पड़ा इंतजार

उन्होंने याद करते हुए कहा, 'मुझे काम के लिए वर्षों तक इंतजार करने की आदत हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दबाजी में कुछ साइन करने के बजाय मैं दो-तीन साल और इंतजार कर सकता हूं।' उन्होंने आगे कहा, 'भगवान की कृपा से, मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जल्द ही मुझे कुछ बहुत अच्छी फिल्में मिलने लगीं।'

'वो फिर कभी दिखा नहीं' के लिए साथ आए नवाजुद्दीन और तिग्मांशु धूलिया

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तिग्मांशु धूलिया एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। दोनों ने इससे पहले कई फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन इस बार वे दर्शकों के लिए कुछ खास ला रहे हैं। तिग्मांशु के निर्देशन में बनने वाली यह फिल्म एक म्यूजिकल थ्रिलर बताई जा रही है, जिसका नाम 'वो फिर कभी दिखा नहीं' है। रिपोर्ट्स के मुताबिक...' यह फिल्म मशहूर कवि और लेखक उदय प्रकाश की इसी नाम की शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है। फिल्म की कहानी और किरदारों से जुड़ी ज्यादातर जानकारी फिलहाल गुप्त रखी गई है। खबर यह भी है कि फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है।'

भविष्य के उद्योगों का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़

नए दौर की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रहा छत्तीसगढ़ भविष्य के उद्योगों पर हमारा फोकस: मुख्यमंत्री साय

एक सत बुलेटिन, रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित तीन दिवसीय 'इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर-2026' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों से आए उद्यमियों, निवेशकों और औद्योगिक प्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ की धरती पर स्वागत करते हुए उन्हें प्रदेश की विकास यात्रा में सहभागी बनने और यहां उपलब्ध निवेश की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज अपनी पारंपरिक औद्योगिक ताकत के साथ नई अर्थव्यवस्था और उभरते उद्योगों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खनिज, ऊर्जा, वन संपदा, पर्याप्त मानव संसाधन और देश के मध्य में अनुकूल भौगोलिक स्थिति हमारी स्वाभाविक ताकत है। राज्य सरकार इन खूबियों को आधुनिक तकनीक, बेहतर अधोसंरचना और निवेशक हितैषी नीतियों से जोड़कर छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक एवं निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की भूमिका केवल उद्योगों के लिए नियामक की नहीं है। हम सरकार को उद्योग और निवेश की राह आसान करने वाले सहयोगी और 'एक्सीलरेटर' के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि निवेश का प्रस्ताव आने से लेकर उद्योग के धरातल पर स्थापित होने तक हर चरण में निवेशकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था मिले। मुख्यमंत्री ने लघु उद्योग भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक आयोजन के लिए रायपुर का चयन किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का विस्तार होने से स्थानीय स्तर पर उद्यमिता बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योग भारती देशभर के 750 से अधिक जिलों में उद्यमियों को संगठित कर उद्योग और

उद्यमिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में भी 1200 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन से जुड़े हैं। 18 से 20 सितम्बर तक आयोजित इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में देशभर के 300 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों की भागीदारी इस आयोजन के महत्व को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक मेला केवल उत्पादों और तकनीकों की प्रदर्शनी नहीं है। यह उद्यमियों के बीच संवाद, अनुभव, नवाचार और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। इसके माध्यम से नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, नई संभावनाओं पर चर्चा होगी और युवाओं को उद्योग तथा उद्यमिता की दुनिया को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उद्योग जगत, निवेशकों और विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें निवेश, उत्पादन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था एक साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में प्रक्रियाओं के सरलीकरण, निवेशकों को प्रोत्साहन, नए एवं उभरते सेक्टरों को बढ़ावा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नीति लागू होने के बाद प्रदेश को बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और प्रसन्नता की बात है कि अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल कोयला, स्टील और सीमेंट जैसे पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार प्रदेश के औद्योगिक आधार को विविधता देने के लिए आईटी, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी सहित विभिन्न नए और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में लगभग 1100 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर परियोजना पर कार्य प्रारंभ होना इस बदलते औद्योगिक परिदृश्य का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर को आधुनिक टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। यहां आधुनिक अधोसंरचना के साथ नए उद्योगों और तकनीक आधारित कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। राज्य में टेक्नोलॉजी हब और इंडस्ट्री एक्सीलेंस हब विकसित करने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसी भी राज्य में उद्योग तभी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जब निवेशकों को नीतिगत स्थिरता के साथ सरल और पारदर्शी प्रक्रियाएं मिलें। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्योग स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में काम किया है, ताकि निवेशकों को विभिन्न कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि उद्योगों को समय पर आवश्यक भूमि, अधोसंरचना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि उद्यमी अपना समय और ऊर्जा प्रक्रियागत जटिलताओं में लगाने के बजाय उत्पादन, नवाचार, विस्तार और रोजगार सृजन में लगाएं।

ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी कामयाबी, जबलपुर और बिहार से दो नाबालिग को तलाशकर परिजनों को सौंपा

एक सत बुलेटिन, कटनी।

पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत एनकेजे पुलिस ने दो अपहृत नाबालिग बालिकाओं को तलाश कर सकुशल दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने एक बालिका को मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले से, जबकि दूसरी को बिहार के मुजफ्फरपुर से तलाश कर थाना लाने के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द किया। लंबे समय से अपनी बेटियों की तलाश कर रहे परिजनों को पुलिस की कार्रवाई से राहत मिली, वहीं परिवारजनों ने एनकेजे पुलिस के प्रयासों की सराहना की। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत अपहृत बालक-बालिकाओं की तलाश और उनकी सुरक्षित दस्तयाबी के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के निर्देशन एवं उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना एनकेजे पुलिस ने दो अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना एनकेजे में दर्ज अपराध क्रमांक 487/26 एवं 500/26, धारा 137(2) बीएनएस के तहत दर्ज मामलों में अपहृत बालिकाओं की तलाश के लिए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया था। पुलिस टीमों ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के साथ ही मोबाइल लोकेशन के आधार पर तकनीकी जानकारी जुटाई। लगातार किए गए प्रयासों के बाद एक बालिका का पता जबलपुर, मध्यप्रदेश में लगाया गया, जबकि दूसरी बालिका को बिहार के मुजफ्फरपुर से तलाश किया गया। दोनों बालिकाओं को दस्तयाब कर थाना एनकेजे लाया गया, जहां आवश्यक कार्रवाई के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बेटियों के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एनकेजे पुलिस के कार्य की सराहना की। इस कार्रवाई में थाना एनकेजे प्रभारी इंचार्ज सउनि सहपाल परतेती, सउनि केवल उइके, प्रधान आरक्षक 368 नरेंद्र मिश्रा, प्रधान आरक्षक 198 आशीष शुक्ला, महिला आरक्षक 376 अस्विता ग्वालवंशी, प्रधान आरक्षक 503 अजय सिंह, महिला आरक्षक 677 वंदना पथरिया, आरक्षक अर्पित पटेल सहित साइबर सेल से शुभम गौतम, अजय साकेत एवं दीपक शर्मा की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस की इस कार्रवाई से ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा एवं अपहृत बच्चों की तलाश के प्रयासों को मजबूती मिली है।

पर्यटन इकाइयाँ लीज़ पर देने की तैयारी, निवेशकों के लिए खुलेगा नया अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की विभिन्न पर्यटन इकाइयों को लीज़ पर दिए जाने की प्रक्रिया को निवेशकों के लिए सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से 'एक्सप्लोर, इनवेस्ट, ट्रांसफार्म' थीम पर प्री-एनआईटी (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में निवेशकों और स्टेकहोल्डर्स को पर्यटन बोर्ड की विभिन्न प्रॉपर्टीज, लीज़ एवं टेंडर प्रक्रिया, उपलब्ध सरकारी प्रोत्साहनों, पीपीपी मॉडल तथा डिजिटल तकनीक के उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाकर पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को नई गति देने की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे के प्रस्तुतीकरण से हुई। उन्होंने उपस्थित निवेशकों एवं स्टेकहोल्डर्स को बोर्ड के विभिन्न होटल, मोटल, रिसॉर्ट एवं पर्यटन इकाइयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रॉपर्टीज की लोकेशन, उपलब्ध सुविधाओं, प्रमुख विशेषताओं तथा पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में उनके विकास की संभावनाओं से अवगत कराया।

हैदराबाद में हैमलीज़ की नई शुरुआत, खुला कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा 10वां फ्लैगशिप स्टोर

एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

हैदराबाद में हैमलीज़ ने खोला अपना सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्टोर; जुबली हिल्स में बच्चों को मिलेगा खिलौनों का जादुई संसार10,000 वर्ग फुट में फैला तीन मंजिला यह स्टोर हैदराबाद में ब्रांड का 10वां और सबसे भव्य डेस्टिनेशन है।स्टोर में 10,000 से अधिक वैश्विक और एक्सक्लूसिव खिलौनों, गेम्स और गिफ्टिंग का शानदार कलेक्शन मौजूद है।बच्चों के मनोरंजन को दोगुना करने के लिए नवंबर 2026 में एक समर्पित 'प्ले एरिया' भी शुरू किया जाएगा।हैदराबाद, सितंबर 2026: दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित खिलौना रिटेलर कंपनी, हैमलीज़ ने हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में अपना नया फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च कर दिया है। यह शहर में हैमलीज़ का 10वां और अब तक का सबसे बड़ा स्टोर है, जिसे बच्चों और परिवारों को खरीदारी के साथ-साथ मनोरंजन का एक अनूठा अनुभव देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।तीन मंजिलों

में फैले इस 10,000 वर्ग फुट के विशाल स्टोर में हैमलीज़ के सिग्नेचर 'थिएटर अनुभव' को जीवंत किया गया है। यहाँ आने वाले बच्चों का स्वागत हैमलीज़ परिवार के आइकॉनिक किरदार जैसे टॉय सोल्जर, पाइरेट्स, इंग्लिशमैन, रैगडॉल और बच्चों के पसंदीदा हैमली व हैटी भालू करेंगे।शानदार ग्रैंड ओपनिंग इवेंटइस भव्य लॉन्चिंग के उपलक्ष्य में 18 सितंबर को शाम 6:30 बजे से एक एक्सक्लूसिव ग्रैंड ओपनिंग इवेंट का आयोजन किया गया। इस शाम को खास बनाने के लिए माय लिटिल पोनी और पीजे मास्क जैसे प्रसिद्ध कार्टून किरदार भी मौजूद रहे। इवेंट में शहर के प्रमुख ग्राहकों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स और मीडिया जगत के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। मेहमानों के लिए डीआईवाई एक्टिविटीज़, इंटरैक्टिव गेम्स और खास फूड व बेवरेज के स्टॉल्स लगाए गए थे।नवंबर में खुलेगा विशेष प्ले एरियाजुबली हिल्स का यह फ्लैगशिप स्टोर सिर्फ खिलौने खरीदने की जगह नहीं, बल्कि बच्चों की कल्पनाओं और खेल को बढ़ावा देने वाला एक डेस्टिनेशन है। इस अनुभव को और भी मजेदार बनाने के लिए नवंबर 2026 में स्टोर के भीतर एक समर्पित प्ले एरिया भी खोला जाएगा, जहाँ बच्चे सुरक्षित माहौल में खेल और नई चीज़ें सीख सकेंगे।हैमलीज़ के बारे में:लंदन में साल 1760 में स्थापित हैमलीज़ दुनिया का सबसे पुराना खिलौना रिटेलर है, जो अपने जादुई इन-स्टोर अनुभवों के लिए जाना जाता है। भारत में हैमलीज़ का संचालन रिलायंस रिटेल द्वारा किया जाता है। रिलायंस रिटेल के नेतृत्व में हैमलीज़ देश का नंबर-वन प्रीमियम टॉय रिटेलर बन चुका है।

स्कूली वाहनों में लापरवाही पड़ी भारी तो होगी कार्रवाई ई-रिक्शा से बच्चों के परिवहन पर कलेक्टर की सख्ती

एक सत बुलेटिन, कटनी।

स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर कटनी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष तिवारी ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले के सभी अशासकीय विद्यालयों में संचालित छात्र परिवहन वाहनों के लिए आवश्यक सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) तथा निजी स्कूलों के संचालकों और प्राचार्यों को सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन सहित मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 और मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जारी निर्देशों के तहत विद्यार्थियों के परिवहन में लगे स्कूली वाहनों में आरटीओ द्वारा प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी एग्जिट द्वार, अग्निशमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन और जीपीएस सिस्टम उपलब्ध होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही वाहनों में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, ताकि क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर परिवहन करने की स्थिति उत्पन्न न हो। स्कूल बसों में पुरुष एवं महिला कंडक्टर की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं।

बच्चों ने रंगों में उकेरी विकसित भारत की तस्वीर, शिक्षा मंत्री यादव ने बढ़ाया उत्साह

रायपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पाटन स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ड्रॉइंग एवं रंगोली प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने रंगों के माध्यम से विकसित भारत के अपने सपनों और कल्पनाओं को जीवंत रूप दिया। छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपनी कला, रचनात्मक सोच और प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।शिक्षा मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक श्री गजेन्द्र यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर विद्यार्थियों द्वारा तैयार चित्रों एवं रंगोलियों का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों से उनकी कलाकृतियों के विषय में संवाद किया और उनकी कल्पनाशीलता एवं रचनात्मकता की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने देश की प्रगति, आत्मनिर्भरता, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान एवं तकनीक सहित विभिन्न विषयों को अपनी कलाकृतियों में स्थान दिया। रंगोली के माध्यम से भी बच्चों ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की अपनी कल्पना को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया। विद्यालय परिसर में सजी रंग-बिरंगी कलाकृतियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और भविष्य के भारत को लेकर उनकी सोच की सुंदर झलक प्रस्तुत की।

महाआरती के साथ गूंजा जनभागीदारी का संदेश

आशीर्वाद के दीपों से जगमगाया कटनी, सेवा संकल्प की रोशनी में एकजुट हुआ शहर

एक सत बुलेटिन, कटनी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़ा के प्रथम दिवस पर नगर पालिक निगम कटनी द्वारा आयोजित 'आशीर्वाद का दिया' दीप प्रज्वलन कार्यक्रम ने शहर को सेवा, समर्पण और जनभागीदारी के प्रकाश से रोशन कर दिया। गुरुवार को आयोजित इस भव्य आयोजन में शहर के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के घरों में भी दीप प्रज्वलित किए गए। दीपों की जगमगाहट के बीच नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए सेवा और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। राज्य शासन के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, विधायक श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, मध्यप्रदेश शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री संजीव सिंह, कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव विश्वकर्मा, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री हरसिमरनप्रीत कौर, वनमंडलाधिकारी श्री गर्वित गंगवार, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दीपक टंडन सोनी, एसडीएम जितेंद्र पटेल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन ने सेवा पखवाड़ा के शुभारंभ

को उत्सव, श्रद्धा और सामाजिक सहभागिता से जोड़ते हुए शहरवासियों के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के घरों से शुरू हुई रोशनी 'आशीर्वाद का दिया' कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास (मल्टी) प्रेमनगर-रोशन नगर परिसर से हुई, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घरों के हितग्राहियों ने अपने आवासों के बाहर दीप प्रज्वलित किए। पक्के घर का सपना साकार होने के बाद अपने आशियाने के बाहर दीप जलाना हितग्राही परिवारों के लिए भावनात्मक और खुशी का विशेष अवसर रहा। दीपों की रोशनी से पूरा आवास परिसर जगमगा उठा और परिवारों में उत्साह एवं उल्लास का वातावरण देखने को मिला। निगम प्रशासन के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल ने प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित परिवारों को सेवा पखवाड़ा के उत्सव से जोड़ने का कार्य किया। हितग्राहियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए जनभागीदारी, सेवा और समर्पण के संकल्प को मजबूत किया। आयोजन के माध्यम से यह संदेश भी सामने आया कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले परिवार भी सामाजिक आयोजनों और सामूहिक सेवा भावना के महत्वपूर्ण सहभागी हैं। घंटाघर से मंदिरों तक दीपों की रोशनी, महाआरती ने बांधा समां कार्यक्रम के अगले चरण में ऐतिहासिक घंटाघर स्मारक स्थल, श्री हनुमान मंदिर समदड़िया सिटी तथा श्री गणेश मंदिर गणेश चौक, सिविल लाइन में दीप प्रज्वलन किया गया। इन प्रमुख स्थलों पर दीपों की रोशनी, नागरिकों की सहभागिता और श्रद्धा का वातावरण देखने को मिला। नागरिकों ने उत्साहपूर्वक दीप जलाकर सेवा, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा के संकल्प को अभिव्यक्त किया।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति भोपाल के लिए, प्रकाशक एवं मुद्रक, **संपादक अमित शर्मा** द्वारा ए -1 माचना कॉलोनी , शा. राजीव गांधी स्कूल के पास, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) पिन - 462016 से प्रकाशित एवं विनर प्रिंटर्स प्लाट 241-242 डायनामिक सेन्टर, एमपी नगर जोन-1 भोपाल से मुद्रित। **स्थानीय संपादक सुनील नायक**, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI- MPHIN/2018/76807/ E-mail-eksatbulletin@gmail.com, डाक पंजीयन नंबर MP/BHOPAL/4-501/2020-22, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें- फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088

सांसद श्री शर्मा ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आंगनवाड़ी केंद्र और निर्माणाधीन वाटर टैंक का किया निरीक्षण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान-2026 के अंतर्गत शुक्रवार को नारियलखेड़ा दशहरा मैदान के पास सामुदायिक केंद्र, वार्ड क्रमांक-12 में जन-कल्याण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सांसद श्री आलोक शर्मा ने सहभागिता कर आमजन से आत्मीय संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं जनसमस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के माध्यम से शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाना और प्रत्येक जायज समस्या का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सेवा, सुशासन और जनविश्वास के संकल्प के साथ समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिविर में नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने की कार्यवाही की गई। अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं को सुगम एवं पारदर्शी तरीके से आमजन तक पहुंचाने के साथ स्थानीय समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है।

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के माध्यम से पात्र नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलोनियों से संबंधित समस्याओं के व्यवस्थित एवं त्वरित निराकरण के लिए कलेक्ट्रेट में समर्पित 'कॉलोनी सेल' का गठन किया गया है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्थानीय निवासियों से अपने क्षेत्रों में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) गठित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए के माध्यम से कॉलोनियों की समस्याओं को साझा मंच पर प्रभावी ढंग से उठाने और उनके निराकरण में सुविधा होगी। उन्होंने अधिकारियों को शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों एवं शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जन-कल्याण शिविर के बाद कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने नारियलखेड़ा क्षेत्र में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-216 का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं, बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा संबंधित कार्यों की जानकारी ली।

भारत भवन में ब.व. कारंत की स्मृति में आज से सजेगा रंगमंच का त्रिदिवसीय 'प्रणति' उत्सव

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

भारत भवन में ब.व. कारंत की स्मृति में तीन दिवसीय 'प्रणति समारोह' का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2026 तक किया जा रहा है। रंगमंडल प्रभाग की ओर से संयोजित यह समारोह भारतीय रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर ब.व. कारंत की रंग-दृष्टि, नाट्य-साधना और रंगमंच को दिए उनके अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करने का अवसर बनेगा। संवाद, परिचर्चा, प्रदर्शनी और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से तीन दिनों तक भारत भवन का परिसर रंग-संवेदना और रंगचिंतन से सराबोर रहेगा। भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रेम शंकर शुक्ल ने बताया कि समारोह का शुभारंभ 19 सितंबर को शाम 6.30 बजे भारत भवन न्यास के अध्यक्ष वामन केन्द्रे करेंगे। उद्घाटन अवसर पर रंगमंडल की रंगयात्रा को केंद्र में रखकर तैयार की गई 'रंग आयाम' प्रदर्शनी का भी शुभारंभ होगा। यह प्रदर्शनी रंगमंडल की दीर्घ रंगयात्रा, उसकी प्रस्तुतियों और रंगकर्म से जुड़े महत्वपूर्ण पड़ावों को दर्शकों के सामने कलात्मक रूप में प्रस्तुत करेगी।

अगस्त माह में ''टाइम ऑफ डे'' टैरिफ के तहत

9 लाख 77 हजार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली 10.53 करोड़ रुपये तक की छूट

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए अगस्त माह लाभदायक रहा। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे (ञ्शष्ठ) टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) में बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है। इसी के तहत अगस्त -2026 में कंपनी कार्यक्षेत्र के कुल 9 लाख 77 हजार 400 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों में कुल ?10.53 करोड़ रुपये की ञ्शष्ठ छूट का सीधा लाभ मिला। इनमें भोपाल रीजन के 7 लाख 94 हजार 972 उपभोक्ताओं को 7 करोड़ 80 लाख 50 हजार रुपये तथा ग्वालियर रीजन के 1 लाख 82 हजार 428 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 72 लाख 82 हजार रुपये की छूट प्रदान की गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगवाएं। स्मार्ट मीटर न केवल ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर नियंत्रण रखने और आर्थिक बचत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

बैरसिया नगर पालिका में नवनियुक्त एल्डरमैनों ने ग्रहण किया पदभार

बैरसिया। नगर पालिका परिषद बैरसिया कार्यालय में बीते गुरुवार को नवनियुक्त एल्डरमैनों ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप सिंह राठौड़ एवं नगर पालिका परिषद के सीएमओ राजेंद्र सक्सेना की उपस्थिति रही पदभार ग्रहण करने के दौरान नव नियुक्त एल्डरमैनों ने नगर के विकास एवं जनहित से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि नगर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए जनहित के मुद्दों को परिषद के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के अधिकारी-कर्मचारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी नवनियुक्त एल्डरमैनों के पदभार ग्रहण करने पर उपस्थित लोगों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की

पीएम विश्वकर्मा की तीसरी वर्षगांठ

हाथकरघा कारीगरों के हुनर को मिला बाजार

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य और पीएम विश्वकर्मा योजना के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुक्रवार को विभिन्न गतिविधियां आयोजित हुईं। संचालनालय हाथकरघा एवं हस्तशिल्प, भोपाल के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को कौशल उन्नयन, आधुनिक उपकरण, ऋण सहायता, डिजिटल सशक्तिकरण और बाजार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना रहा। संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम द्वारा मृगनयनी के सभी एम्पोरियम में पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए विशेष प्रदर्शनी लगाई गई।

इसमें मध्यप्रदेश के अलावा गुजरात, राजस्थान, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली स्थित छह मृगनयनी केन्द्र में भी स्थानीय पीएम विश्वकर्मा कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला। इससे कारीगरों को

नए बाजार और व्यापक ग्राहक वर्ग से जुड़ने का अवसर मिला। इस अवसर पर ट्राइबल आर्टिजन्स इम्पेलमेंट मेला आयोजित किया गया। ट्राइफेड के सहयोग से हुए मेले में 41 जनजातीय कारीगर शामिल हुए। इनमें पांच कारीगरों ने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान कारीगरों से कुल 38 हजार रुपए के उत्पादों की खरीद की गई। कार्यक्रम में ट्राइफेड की मध्यप्रदेश महाप्रबंधक-सह-क्षेत्रीय प्रबंधक प्रीति मैथिल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल में 'विश्वकर्मा संवाद' का आयोजन किया गया। इसमें कारीगरों, विद्यार्थियों और नीति विशेषज्ञों ने पारंपरिक शिल्प और आजीविका के अवसरों पर संवाद किया। चंदेरी की कारीगर किरण कोली और उज्जैन की कारीगर यादमीन बी का सम्मान किया गया। दोनों कारीगरों ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। परिसर में उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए लगाए गए स्टॉल से 40 हजार रुपए की बिक्री हुई।

रात में राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में हो रही परेशानी, पंचायत से लाइट लगाने की मांग

■ एक सत बुलेटिन, **बैरसिया।**

जनपद पंचायत बैरसिया के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत डुंगरिया में मेन चौराहे से नीचे नदी घाट की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग एवं आसपास के परिसर में रात के समय पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से अंधेरा छाया रहता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यहां लंबे समय से रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण रात में आने-जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि चौराहे से नदी घाट की ओर जाने वाले क्षेत्र में जगह-जगह कचरा एवं गंदगी भी दिखाई देती है। ऐसे में अंधेरा होने के कारण लोगों को इस रास्ते से गुजरने में काफी परेशानी होती है। विशेषकर देर शाम और रात के समय पैदल आने-जाने वाले ग्रामीणों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है।ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से मांग की है कि चौराहे से नदी

घाट तक तथा आसपास के सार्वजनिक परिसर का निरीक्षण कर आवश्यक स्थानों पर स्ट्रीट लाइट अथवा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कराई जाए। साथ ही नदी घाट एवं आसपास जमा कचरे की नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्रामीणों और राहगीरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिल सके।

भोपाल में 82 आवारा श्वान पकड़े, नसबंदी के बाद 85 छोड़े

भोपाल। नगर निगम के डॉग स्क्वाड ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 82 आवारा श्वानों को पकड़कर नसबंदी केंद्रों में भेजा। नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण के बाद 85 श्वानों को वापस उसी स्थान पर छोड़ा गया। संस्कृति जैन के निर्देश पर की गई कार्रवाई में 21 श्वानों को एबीसी सेंटर, 34 को आदमपुर एबीसी सेंटर और 27 श्वानों को अरवलिया एबीसी सेंटर भेजा गया। निगम के अनुसार आवारा श्वानों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण की कार्रवाई लगातार जारी है।

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर के निर्देशन में जिले में अब तक 59 निरीक्षण

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिले के विभिन्न शासकीय संस्थानों एवं जनसुविधाओं का मैदानी निरीक्षण किया जा रहा है। अभियान के लिए 18 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार संस्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभियान के तहत राशन दुकानों शासकीय अस्पतालों छात्रावासों, विद्यालयों आंगनवाड़ियों सहित विभिन्न शासकीय संस्थानों का

निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर संस्थानों में उपलब्ध व्यवस्थाओं, सेवाओं और आवश्यक सुविधाओं का परीक्षण किया तथा निर्धारित जानकारी दर्ज की। निरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन संचालित किया जा रहा है। अधिकारी निरीक्षण के दौरान आवश्यक जानकारी और फोटोग्राफ एप्लीकेशन पर अपलोड कर रहे हैं इससे निरीक्षण कार्य की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा रही है।

भोपाल, अशोकनगर एवं इटारसी स्टेशनों पर औचक टिकट जाँच अभियान चलाया गया

बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों पर 1.26 लाख से अधिक जुर्माना

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भोपाल मंडल द्वारा विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों में नियमित एवं आकस्मिक टिकट जाँच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भोपाल मंडल के अशोकनगर, इटारसी एवं भोपाल रेलवे स्टेशनों पर तीन विशेष टिकट जाँच अभियान आयोजित किए गए।

अशोकनगर स्टेशन पर पहली बार किलाबंदी टिकट जाँच

अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर पहली बार किलाबंदी टिकट जाँच अभियान आयोजित किया गया। मुख्य टिकट निरीक्षक श्री नरेंद्र जाटव के नेतृत्व में 6 टिकट जाँच कर्मचारियों द्वारा की गई जाँच के दौरान 66 यात्री बिना टिकट अथवा अनियमित यात्रा करते पाए गए। इन यात्रियों से 47,200/- का रेल राजस्व वसूल किया गया। इटारसी स्टेशन पर किलाबंदी टिकट जाँच इटारसी रेलवे स्टेशन पर मुख्य टिकट निरीक्षक श्री हेमंत सोनी के नेतृत्व में 11 टिकट जाँच कर्मचारियों के सहयोग से किलाबंदी टिकट जाँच अभियान चलाया गया। जाँच के दौरान 76 यात्री बिना टिकट अथवा अनियमित यात्रा करते पाए गए, जिनसे 61,090/- का रेल राजस्व वसूल किया गया। भोपाल स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट जाँच भोपाल रेलवे स्टेशन पर आयोजित रेलवे मजिस्ट्रेट जाँच के दौरान मुख्य टिकट निरीक्षक श्री सुनील वर्गीस के साथ 4 टिकट जाँच कर्मचारियों द्वारा प्रभावी टिकट जाँच की गई। इस दौरान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा

करने वाले यात्रियों से 18,200/- का रेल राजस्व वसूल किया गया। इस प्रकार इन तीनों विशेष टिकट जाँच अभियानों में कुल 218 यात्रियों से 1,26,490/- का रेल राजस्व वसूल किया गया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आयोजित रेलवे मजिस्ट्रेट जाँच के दौरान रेलवे मजिस्ट्रेट, भोपाल श्री अनुराग खरे के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग, रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन तथा ट्रेनों में भी औचक निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम द्वारा गाड़ी संख्या 12174 उद्योगनगरी एक्सप्रेस एवं 22538 कुशीनगर एक्सप्रेस में खानपान एवं वेंडिंग व्यवस्था, साफ-सफाई तथा भोजन की गुणवत्ता का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही खानपान सामग्री की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों के अनुपालन की जाँच की गई। सीनियर डीसीएम श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्रियों को सुगम एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा यात्रियों को निर्धारित टिकट के साथ यात्रा करने के लिए जागरूक करने हेतु इस प्रकार के आकस्मिक टिकट जाँच अभियान निरंतर जारी रखे जा रहे हैं।

स्वामी एक सत प्रयास जनकल्याण समिति भोपाल के लिए, प्रकाशक एवं मुद्रक, **संपादक अमित शर्मा** द्वारा ए -1 माचना कॉलोनी , शा. राजीव गांधी स्कूल के पास, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) पिन - 462016 से प्रकाशित एवं विनर प्रिंटर्स प्लाट 241-242 डायनामिक सेन्टर, एमपी नगर जोन-1 भोपाल से मुद्रित। **स्थानीय संपादक सुनील नायक**, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI- MPHIN/2018/76807/ E-mail-eksatbulletin@gmail.com, डाक पंजीयन नंबर MP/BHOPAL/4-501/2020-22, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें- फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9691653088